श्रावण कृष्ण पक्ष-3, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-10, अंक - 27 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांकः म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल
01 अगस्त 2026 शनिवार

आज का मौसम
30.8 अधिकतम
23.5 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

Page-7

प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक और अराजक राजनीति का संकट

प्रसंगवश

राजेश सिरोठिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के घटनाक्रम में ऐसा राजनीतिक दांव चला है, जिसने केवल विपक्ष की तत्काल रणनीति को ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में विरोध की बदलती संस्कृति पर भी नई बहस छेड़ दी है। इसे केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया मानना भूल होगी। यह उस प्रश्न का उत्तर भी है कि लोकतंत्र में असहमति की सीमा क्या होनी चाहिए और विरोध कब अराजकता में बदलने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया संदेश केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं कही जा सकती। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इसने उस बहस की दिशा ही बदल दी, जिसे विपक्ष सरकार बनाम युवाओं के संघर्ष के रूप में स्थापित करना चाहता था। '

पिछले दिनों जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़े प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई को विपक्ष ने लोकतंत्र पर हमला बताकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। संसद के भीतर भी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे हमले हुए। यह विपक्ष का अधिकार है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछे ही जाने चाहिए। लेकिन एक सवाल विपक्ष से भी पूछा जाना चाहिए। क्या कानून तोड़ने, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने और सार्वजनिक जीवन की सारी मर्यादाएं लांघ देने को भी लोकतांत्रिक अधिकार माना जा सकता है? इन प्रदर्शनों में शामिल कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि उनकी दिवंगत मां तक के लिए अत्यंत अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। यह केवल राजनीतिक असहमति नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की गरिमा से विचलन था। भीड़ के मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि सामूहिक उत्तेजना में व्यक्ति कई बार वह सब कर बैठता है, जिसे वह सामान्य परिस्थितियों में स्वयं भी स्वीकार नहीं करता। ऐसे आंदोलनों में सबसे अधिक जोखिम उन युवाओं का होता है, जिन्हें राजनीतिक नेतृत्व आगे कर देता है, जबकि परिणामस्वरूप कानूनी और सामाजिक दुष्परिणाम भी प्रायः उन्हीं को भुगतने पड़ते हैं।

यहीं प्रधानमंत्री मोदी का कदम राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम संदेश में गालियों का जवाब गालियों या प्रतिशोध से नहीं दिया। उन्होंने युवाओं से घर लौटने, अपने माता-पिता की चिंता समझने और अपने भविष्य पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने संकेत दिया कि नादानी में हुई गलती से किसी युवा का पूरा जीवन निर्धारित नहीं होना चाहिए। यह प्रतिक्रिया केवल व्यक्तिगत उदारता का प्रदर्शन नहीं थी। राजनीतिक दृष्टि से इसने उस नैरेटिव को भी कमजोर कर दिया, जिसमें कठोर कार्रवाई के आधार पर सरकार को 'दमनकारी' साबित करने की कोशिश की जा सकती थी।

मैं न तो किसी व्यक्ति का भक्त हूं और न किसी दल का प्रवक्ता। यह विश्लेषण किसी व्यक्ति या दल के समर्थन अथवा विरोध का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक राजनीति के उस चरित्र का है, जिसकी कसौटी पर हर दल और हर नेता को परखा जाना चाहिए।' पत्रकारिता का दायित्व व्यक्तियों से ऊपर उठकर घटनाओं और उनके दूरगामी प्रभावों का विश्लेषण करना है। उसी दृष्टि से देखें तो इस पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री का संदेश भारतीय लोकतंत्र को अधिक परिपक्व बनाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत प्रतीत होता है। असहमति लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन असहमति और अराजकता समानार्थी नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है कि जब भी राजनीतिक दल अल्पकालिक लाभ के लिए भीड़ की भावनाओं को भड़काने की राजनीति करते हैं, तब उसके परिणाम अंततः पूरे समाज को भुगतने पड़ते हैं। नेपाल, बांग्लादेश और दुनिया के अनेक देशों के अनुभव बताते हैं कि एक बार अराजकता का जिन्न बोतल से बाहर निकल जाए तो वह किसी दल, किसी नेता या किसी विचारधारा का नहीं रह जाता। शुरुआत में वह विरोधियों को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंततः वही आग अपने संरक्षकों के दरवाजे तक भी पहुंच जाती है।

युवाओं को मोहरा न बनाएं राजनीतिक दल

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह रही है कि यहां सत्ता परिवर्तन चुनाव से होता है, सड़कों की अराजकता से नहीं। विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार की आलोचना करे, उसे कठघरे में खड़ा करे और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करे। किंतु यदि राजनीति का आधार केवल उत्तेजना, व्यक्तिगत घृणा और संस्थाओं के प्रति अविश्वास बन जाएगा, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र को ही होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल युवाओं को मोहरा नहीं, भविष्य का निर्माता समझें। उन्हें गुस्से का हथियार नहीं, लोकतंत्र का सजग नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें। विरोध कीजिए, लेकिन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर। सत्ता को चुनौती दीजिए, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़े बिना। यही परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। राजनीति में कई बार सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रतिशोध नहीं, बल्कि संयम होता है। यदि इस पूरे घटनाक्रम से देश की राजनीति यह सीख ले सके कि लोकतंत्र की असली ताकत संवाद, कानून और मर्यादा में है, तो यह केवल किसी एक नेता की नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जीत होगी।

न्यूज विंडो

राष्ट्रपति भवन में 'एट होम' कार्यक्रम में शामिल होंगी भोपाल की पूनम

भोपाल, दोपहर मेट्रो। सामाजिक सरोकारों और दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाने वाली भोपाल की सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्दीप सोशल वेलफेयर सोसायटी की संस्थापक पूनम श्रोती को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के विशेष 'एट होम' समारोह में शामिल होने का आधिकारिक आमंत्रण मिला है। 15 अगस्त को होने वाले इस प्रतिष्ठित समारोह में उनकी सहभागिता सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को मिली महत्वपूर्ण पहचान के तौर पर देखी जा रही है।

बदलाव: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 194 रुपए तक सस्ता

भोपाल, दोपहर मेट्रो। देशभर में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में इसकी कीमत 190 से 194 रुपए तक कम हुई है। भोपाल में अब कमर्शियल सिलेंडर 2743 रुपए में मिलेगा। कीमतों में कमी से होटल, रेस्टॉरेंट और कैटरिंग कारोबार को राहत मिलने की उम्मीद है।होटल और रेस्टॉरेंट संचालकों का कहना है कि कुछ महीनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से संचालन लागत बढ़ गई थी। इसकी वजह से कई जगह खाने और कैटरिंग सेवाओं की कीमतें भी 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाई गई थीं। अब सिलेंडर सस्ता होने से आने वाले समय में ग्राहकों को कुछ राहत मिल सकती है।

परासिया कफ सिरप कांड में आरोपी ज्योति सोनी को जमानत

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के चर्चित मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल 'अपना मेडिकल स्टोर' की प्रोपराइटर ज्योति सोनी को 271 दिन बाद जमानत मिल गई है। शुक्रवार को न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर कर ली, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। यह मामला वर्ष 2025 में कई बच्चों की मौत के बाद पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना था। घटना के बाद शासन ने विशेष जांच दल गठित कर मामले की विस्तृत जांच कराई थी। एसआईटी ने 3 नवंबर 2025 को ज्योति सोनी को गिरफ्तार किया था।

आज का कार्टून

टूथपेस्ट से लेकर पेंट तक, सब कुछ महंगा करने की तैयारी

फेस्टिवल सीजन में झटका, जंग का इम्पैक्ट ग्राहकों पर डालेंगी कंपनियां

नई दिल्ली, एजेंसी

जैसे ही मानसून विदा होगा भारतीय त्योहारों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर देंगे। घर के रंग-रोगन कराने से लेकर रसोई में नए साजो-सामान लाने की योजना बनने लगेगी। लेकिन, पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव आने वाले त्योहारी सीजन में आम उपभोक्ता के जेब पर भारी पड़ने वाला है। इसका कारण यह है कि कंपनियों ने टूथपेस्ट, कपड़े धोने के डिटर्जेंट और घर की दीवारों पर लगने वाले पेंट से लेकर टायरों तक के दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसान, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, हैवेल्स और डोडला डेयरी समेत कम से कम 8 बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ाएंगी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से कच्चे माल और कमोडिटी की लागत बढ़ गई है। इससे कंपनियों के खर्च में इजाफा हो गया है। बढ़ी हुई लागत का भार कंपनियां आम आदमी पर ही डालेंगी। नोमुरा होल्डिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री सोनल वर्मा का कहना है कि इनपुट लागत और कंपनियों के मार्जिन पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कीमतों में कुछ बढ़ोतरी होना लगभग तय है।

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने संकेत दिया है कि अगले कुछ महीनों में डिटर्जेंट और बर्तन धोने वाले बार जैसे उत्पादों की कीमतों में सीमित बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी विम, सर्फ एक्सेल, रिन और व्हील जैसे ब्रांड बनाती हैं। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी निरंजन गुप्ता ने विश्लेषकों से कहा कि बाहरी अस्थिरता के चलते कच्चे तेल से जुड़े डेरिवेटिव की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में होम केयर उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों में चरणबद्ध तरीके से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं।

एशियन पेंट्स और डोडला डेयरी समेत कम से कम सात अन्य कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही हैं। इसकी जानकारी कंपनियों ने तिमाही नतीजों के बाद आयोजित कॉन्फ्रेंस कॉल और मीडिया ब्रीफिंग में दी है। ऐसा होने पर घर के रंग-रोगन के लिए जरूरी पेंट के साथ ही साबून, टूथपेस्ट और घी-मक्खन जैसे रोज इस्तेमाल होने वाले उत्पाद महंगे हो जाएंगे।

चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही हैं होम केयर उत्पादों की कीमतें

मांग मजबूत तो बोझ ग्राहकों पर

रक्षाबंधन, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली, ये चार त्योहार कंपनियों की तिजोरी के लिए सबसे अहम होते हैं। पूरे साल की कुल बिक्री का एक-तिहाई हिस्सा इसी दौरान आता है। कंपनियां अपनी बढ़ी हुई इनपुट लागत का बोझ सीधा आम जनता की जेब पर डालने जा रही हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ता मांग अब तक स्थिर बनी हुई है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक जून में खुदरा बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 6% बढ़ी, जो मई के मुकाबले बेहतर रही। द नॉलेज कंपनी के चेयरमैन अरविंद सिंघल ने कहा कि फिलहाल मांग संतोषजनक स्थिति में है। हालांकि, कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी के असर और कमजोर मानसून से जुड़े जोखिमों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

'मैं शर्मिंदा हूं': पीएम को अपशब्द कहने वाली लड़की ने मांगी माफी

नई दिल्ली, एजेंसी। जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाली लड़की का माफी मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात जेन-जी को संबोधित करते हुए अपशब्दों के लिए बच्चों को माफ करने की अपील की थी। वीडियो में लड़की अपने कहे गए अपशब्दों के लिए माफी मांगने के साथ कहती नजर आ रही है कि वह दिल्ली के कनॉट प्लेस में चल रहे प्रदर्शन में मौजूद लोगों के प्रभाव में आ गई थीं।

नाम पूछा फिर बरसाईं गोलियां, दूसरे घायल मजदूर ने भी तोड़ा दम

कुलगाम। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों के हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हमले में अब दोनों मजदूरों की मौत हो चुकी है। दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और कुलगाम के केलम इलाके में एक ईंट भट्ठे पर काम करते थे।शुक्रवार देर शाम आतंकियों ने दोनों मजदूरों को निशाना बनाया। हमले में दीपक रात्रे की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 28 वर्षीय भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था।

हरदा में बलराम कृषि महोत्सव, किसानों को दी आधुनिक तकनीकों की जानकारी

हरदा, एजेंसी। हरदा की कृषि उपज मंडी प्रांगण में आज 'बलराम कृषि महोत्सव' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और किसानों को संबोधित किया। महोत्सव का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत उपकरणों और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। कार्यक्रम में कृषि यंत्रों और नई तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई गई। विभिन्न विभागों ने किसानों को योजनाओं की जानकारी दी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया, वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने खेती से जुड़ी नवीन जानकारियां और मार्गदर्शन प्रदान किया।

मुश्किल में फंसे पूर्णिया सांसद, दिल्ली के थाने में शिकायत

संसद में प्रदर्शन मामले में पप्पू यादव पर एफआईआर

नई दिल्ली, एजेंसी

संसद परिसर में कथित राम मंदिर चंदा गबन मामले को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।यह शिकायत सूर्य मैथिल ने दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि संसद परिसर के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव ने धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रदर्शन में भगवान रामलला विराजमान की तस्वीर को पैरों के नीचे रखा गया, जिससे सनातन को मानने वालों की भावनाएं आहत हुई हैं।

मेट्रो एंकर

सर्वोच्च अदालत ने कहा - बेटे और बेटी के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव संविधान के विपरीत

अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं की जा सकतीं विवाहित बेटियां: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि शादी के बाद बेटी का अपने मायके से रिश्ता समाप्त नहीं हो जाता। अदालत ने कहा कि अनुकंपा (करुणामूलक) नियुक्ति के मामलों में केवल तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई विवाहित बेटियों को ही पात्र मानना और अन्य विवाहित बेटियों को बाहर रखना संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने बिहार सरकार की उस नीति को असंवैधानिक ठहराया, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के लिए विवाहित बेटियों में केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को ही पात्र माना गया था। अदालत ने कहा कि किसी महिला के साथ केवल उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान बेटा और बेटी के बीच समान अधिकार की बात करता है। पहले भी कई फैसलों में अदालत यह स्पष्ट कर चुकी है कि केवल बेटी होने या उसके विवाहित होने के आधार पर उसके अधिकार कम नहीं किए जा सकते। इसलिए यह मान लेना कि शादी के बाद बेटी का अपने माता-पिता या मायके से कोई संबंध नहीं रहता, कानून और संविधान दोनों की भावना के विपरीत है। अदालत ने बिहार सरकार की उस दलील को भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि विवाह के बाद बेटी सामान्यतः अपने ससुराल में रहने लगती है। कोर्ट ने कहा कि यह केवल एक सामाजिक धारणा हो सकती है, लेकिन कानूनी आधार नहीं। कई परिस्थितियों में विवाहित बेटियां भी अपने माता-पिता पर आश्रित होती हैं या उनका परिवार उनके मायके से जुड़ा रहता है। इसलिए केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

आठ सप्ताह में करें निराकरण

यह फैसला बिहार की एक महिला की याचिका पर आया। महिला के पिता बिहार सरकार में कर्मचारी थे और उनके निधन के बाद उसने अनुकम्पा नियुक्ति की मांग की थी। लेकिन अधिकारियों ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि वह न तो तलाकशुदा है और न ही परित्यक्ता। महिला ने अदालत को बताया कि वह अपने मायके में रह रही है तथा उसकी मां और भाई ही उसका सहारा हैं, हालांकि उसका तलाक अभी कानूनी रूप से अंतिम नहीं हुआ है।सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले और राज्य सरकार द्वारा महिला का आवेदन खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह महिला के करुणामूलक नियुक्ति के दावे पर सभी तथ्यों और योग्यता के आधार पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेकर उचित कार्रवाई करे।

सुभाष नगर ओवरब्रिज पर उभरे गहरे गड्ढों से झांक रहे हैं लोहे के सरिए

रोजाना हजारों वाहन चालकों की जान जोखिम में, स्थानीय लोगों ने तत्काल मरम्मत और संरचनात्मक जांच की उठाई मांग

भोपाल. दोपहर मेट्रो

राजधानी भोपाल का सुभाष नगर ओवरब्रिज इन दिनों बदहाल स्थिति के कारण हादसों का इंतजार करता नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच ओवरब्रिज की सड़क पर कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई जगहों पर पुल के भीतर लगी लोहे की सरिया बाहर निकल आई है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल इस ओवरब्रिज से प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं, लेकिन सड़क की जर्जर हालत वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सबसे ज्यादा खतरा दोपहिया वाहन चालकों को है। बारिश का पानी गड्ढों में भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, पुल की सतह पर कई जगह दरारें भी दिखाई देने लगी हैं। लगातार बारिश के कारण सड़क की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग और प्रशासन की ओर से अब तक मरम्मत का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ओवरब्रिज की मरम्मत नहीं कराई गई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। नागरिकों ने लोक निर्माण विभाग और प्रशासन से पुल का तत्काल निरीक्षण कराने, गड्ढों को भरने, बाहर निकली सरिया को सुरक्षित करने और पुल की संरचनात्मक जांच कराने की मांग की है।

शाहपुरा तालाब में हुई मौत के पीछे कई पहलुओं की जांच में जुटी पुलिस

सरकारी नौकरी का दबाव और टूटते सपने, IIT इंजीनियर प्रियांशु की मौत ने खड़े किए कई सवाल

भोपाल. दोपहर मेट्रो

आईआईटी कानपुर से पढ़ाई पूरी करने वाले 26 वर्षीय प्रियांशु जैन की शाहपुरा तालाब में डूबने से हुई मौत ने सरकारी नौकरी, पारिवारिक अपेक्षाओं और युवाओं पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रियांशु का हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से टैक्स असिस्टेंट पद पर चयन हुआ था और जल्द ही उसकी जॉइनिंग होने वाली थी।

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, प्रियांशु को निजी क्षेत्र में करीब 25 लाख रुपये सालाना पैकेज का प्रस्ताव भी मिला था, लेकिन परिवार ने उसे सरकारी नौकरी की तैयारी जारी रखने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि उसने यूपीएससी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी थीं, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से वह मानसिक तनाव में था।

सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय चयन आयोग के माध्यम से उसे इंस्पेक्टर पद भी मिला था, लेकिन पारिवारिक कारणों से उसने जॉइनिंग नहीं की। पिछले कुछ समय से वह एंजायटी और डिप्रेशन से जूझ रहा था और शुक्रवार को इलाज के लिए बंसल अस्पताल जाने की बात कहकर घर से निकला था। बाद में शाहपुरा तालाब के पास उसकी स्कूटी मिली और पानी से उसका शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

25 लाख के पैकेज का ऑफर ठुकराने से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक की कहानी

करोड़ों के सपनों के बीच बढ़ता मानसिक दबाव

आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से निकलने वाले युवाओं पर अक्सर बेहतर करियर, ऊंचे पद और सरकारी नौकरी हासिल करने का दबाव रहता है। प्रियांशु जैन के मामले में भी ऐसी ही परिस्थितियां सामने आ रही हैं। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, उन्हें निजी क्षेत्र में 25 लाख रुपये सालाना पैकेज का ऑफर मिला था, लेकिन सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देने के कारण उन्होंने वह अवसर छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने और लगातार बढ़ते दबाव ने उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं पर करियर को लेकर बढ़ती अपेक्षाएं कई बार गंभीर मानसिक तनाव का कारण बन जाती हैं।

पुलिस कई पहलुओं पर कर रही पड़ताल

चूनाभट्टी पुलिस के अनुसार, प्रियांशु जैन पिछले कुछ वर्षों से मानसिक तनाव और एंजायटी से जूझ रहे थे। करीब दो-तीन साल पहले उनका इलाज भी चल चुका था। शुक्रवार को वह बंसल अस्पताल जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन बाद में शाहपुरा तालाब के पास उनकी स्कूटी मिली। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे कौन-कौन से कारण जिम्मेदार रहे। परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा।

कुरवाई स्टेशन की जीआरपी जांच में जुटी

चलती पुष्पक एक्सप्रेस के बाहर 9 किमी तक झूलता रहा शव, बीना स्टेशन पर मचा हड़कंप

भोपाल/बीना. दोपहर मेट्रो

भोपाल से ललितपुर जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। ट्रेन के वॉशरूम की खिड़की से बाहर एक युवक का शव गमछे के सहारे लटका मिला, जो करीब नौ किलोमीटर तक ट्रेन के बाहर झूलता रहा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन और जीआरपी में हड़कंप मच गया।

घटना का खुलासा उस समय हुआ, जब ट्रेन कुरवाई रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर ने वॉशरूम की खिड़की से बाहर लटके शव को देखा और तुरंत ट्रेन के गार्ड व बीना स्टेशन को सूचना दी। इसके बाद रात 12:03 बजे बिना निर्धारित ठहराव के ट्रेन को बीना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर रोका गया।

जीआरपी ने शव को नीचे उतारकर तलाशी ली, जिसमें मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ग्राम पदनिया निवासी 30 वर्षीय गुरुवर सिंह के रूप में हुई। सहयात्रियों के मुताबिक, वह भोपाल स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ था। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक ने वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद किया था। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना देकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कुरवाई रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे स्टेशन मास्टर की सतर्कता ने इस पूरी घटना का खुलासा किया। रात के समय जैसे ही उनकी नजर ट्रेन के वॉशरूम की खिड़की से बाहर लटके शव पर पड़ी, उन्होंने तुरंत गार्ड और रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही बीना स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया गया। पुष्पक एक्सप्रेस का बीना स्टेशन पर कोई निर्धारित ठहराव नहीं था, लेकिन आपात स्थिति को देखते हुए ट्रेन को रात 12:03 बजे प्लेटफॉर्म नंबर चार पर रोका गया। इसके बाद जीआरपी और रेलवे अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन मास्टर की सूझबूझ से मामले की जानकारी समय रहते मिल सकी।

छत्तीसगढ़ का रहने वाला था युवक, जांच जारी

जीआरपी की जांच में मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ग्राम पदनिया निवासी 30 वर्षीय गुरुवर सिंह के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसकी जेब से आधार कार्ड मिला, जिससे पहचान संभव हो सकी। हालांकि, उसके पास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, लेकिन मौत के कारणों को लेकर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जीआरपी थाना प्रभारी बी.बी.एस. परिहार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है।

एक महीने में जीआरपी ने 16 बच्चों को सुरक्षित निकाला, अपहरण के तीन केस का भी खुलासा

भोपाल. दोपहर मेट्रो

भोपाल रेलवे स्टेशन पर जुलाई महीने भर चलाए गए 'ऑपरेशन हमदर्द' के तहत जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। 31 दिनों तक चले इस विशेष अभियान में कुल 16 बच्चों को सुरक्षित तलाशकर उनके परिजनों तक पहुंचाया गया। इनमें तीन बच्चे ऐसे थे, जिनके अपहरण के मामले विभिन्न राज्यों में दर्ज थे, जबकि 13 बच्चे रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और ऑटो में लावारिस या भटकी हुई अवस्था में मिले।

पुलिस अधीक्षक रेल अंकित जायसवाल के निर्देशन में जीआरपी भोपाल ने रेलवे स्टेशन परिसर में लगातार सघन जांच और सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान बेसहारा और बेघर लोगों की भी पहचान की गई। अभियान के दौरान बिहार की एक माह की बच्ची, गुजरात की एक 17 वर्षीय किशोरी और उत्तर प्रदेश की एक अन्य किशोरी को सुरक्षित बरामद किया गया। इन तीनों के अपहरण के मामले संबंधित राज्यों में दर्ज थे। जीआरपी ने बच्चों को सुरक्षित दस्तयाब कर संबंधित राज्यों की पुलिस और उनके परिजनों को सौंप दिया। इसके अलावा, 13 अन्य बच्चे रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और ऑटो में भटके हुए मिले। इनमें मध्य प्रदेश के नौ, उत्तर प्रदेश के तीन और राजस्थान के दो बच्चे शामिल हैं। सुरक्षित बरामद किए गए कुल 16 बच्चों में 11 बालिकाएं और पांच बालक हैं। जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर अकेले या संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने वाले बच्चों की पहले काउंसलिंग और पहचान की जाती है। इसके बाद संबंधित पुलिस और परिजनों से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित सुपुर्द किया जाता है। पुलिस का मानना है कि 'ऑपरेशन हमदर्द' न केवल भटके बच्चों को परिवारों से मिलाने का माध्यम है, बल्कि मानव तस्करी, बाल अपराध और अपहरण जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।

42 अपराध, कई बार जेल... फिर भी नहीं थमा नशे का कारोबार अब बिना ट्रायल छह महीने सलाखों के पीछे रहेगा 'शैलू'

भोपाल. दोपहर मेट्रो

गांजा तस्करी के मामलों में बार-बार गिरफ्तारी और जेल की सजा भी जिस अपराधी को अवैध कारोबार से नहीं रोक सकी, उसके खिलाफ भोपाल पुलिस ने अब सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई की है। बागसेवनिया के हिस्ट्रीशीटर शैलू उर्फ शैलेश संकत (कंजर) पर पहली बार पिट-एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है। भोपाल संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने उसके खिलाफ छह महीने के निरोध (डिटेंशन) का आदेश जारी किया है। इसके तहत उसे केंद्रीय जेल, इंदौर में रखा जाएगा।

बागसेवनिया थाना प्रभारी अमित सोनी के मुताबिक, 35 वर्षीय शैलेश संकत वर्ष 2020 से लगातार गांजा तस्करी में सक्रिय था। वह बाहरी राज्यों से मादक पदार्थ मंगवाकर भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था। पुलिस की नजर से बचने के लिए उसने एजेंटों और बिचौलियों का एक नेटवर्क भी तैयार कर रखा था, जिसके जरिए पूरे कारोबार का संचालन किया जाता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शैलेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के पांच मामलों समेत कुल 42 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में जेल से रिहा होने के कुछ ही दिनों बाद उसने फिर से नशीले पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी थी। इसके बाद बागसेवनिया पुलिस ने उसके आपराधिक इतिहास और तस्करी से जुड़े नेटवर्क का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर भोपाल संभाग आयुक्त को भेजा। प्रस्ताव की समीक्षा के बाद शैलेश के खिलाफ पिट-एनडीपीएस एक्ट, 1988 की धारा 3(1) के तहत निरोध आदेश जारी किया गया। भोपाल पुलिस का दावा है कि जिले में किसी ड्रग तस्कर के खिलाफ इस कानून के तहत यह पहली कार्रवाई है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि यह कदम उन आदतन तस्करों के लिए सख्त संदेश है, जो जेल से छूटने के बाद दोबारा अपराध की दुनिया में लौट आते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, पिट-एनडीपीएस एक निरोधात्मक कानून है, जिसका उद्देश्य संगठित और आदतन ड्रग तस्करों की गतिविधियों को रोकना है।

मेट्रो एंकर

राज्य सूचना आयोग ने तीन मामलों में मांगा जवाब

आरटीआई विवाद में फंसा चीता प्रोजेक्ट, डायरेक्टर से मांगा जवाब

भोपाल. दोपहर मेट्रो

कूनो नेशनल पार्क और चीता प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक नहीं करने के आरोपों के बीच राज्य सूचना आयोग ने चीता प्रोजेक्ट के डायरेक्टर उत्तम शर्मा को तलब किया है। राज्य सूचना आयुक्त राजेश भट्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे की शिकायत पर सुनवाई करते हुए चार में से तीन मामलों में डायरेक्टर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2024 में चीतों को बेहोश करने की अनुमति, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, घायल चीतों के ऑपरेशन के बाद की स्थिति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कूनो में निर्माण कार्यों में उपयोग की गई खनिज सामग्री, चीता प्रोजेक्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री की अनुमति और चीता अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों से संबंधित जानकारियां आरटीआई के तहत मांगी गई थीं, लेकिन विभाग ने जानकारी देने से इन्कार कर दिया।

जानकारी रोकने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और 8(1)(जे) का हवाला दिया गया। वहीं, कुछ सूचनाओं के लिए अनुचित शुल्क मांगे जाने का भी आरोप है। सुनवाई के दौरान अजय दुबे ने आयोग को दस्तावेज सौंपते हुए दावा किया कि प्रोजेक्ट प्रभारी ने स्वयं ही लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी की भूमिका निभाते हुए नियमों के विपरीत आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता ने आरटीआई अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उत्तम शर्मा के खिलाफ जुर्माना, विभागीय जांच और क्षतिपूर्ति की मांग की है। राज्य सूचना आयोग अब पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है।

इन जानकारियों को लेकर उठा विवाद

आरटीआई के तहत कूनो नेशनल पार्क और चीता प्रोजेक्ट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई थीं। इनमें वर्ष 2024 में चीतों को बेहोश करने की अनुमति, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, घायल चीतों के ऑपरेशन के बाद की मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चीता अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टरों व संसाधनों की जानकारी शामिल थी। इसके अलावा, कूनो में निर्माण कार्यों में इस्तेमाल खनिज सामग्री और चीता प्रोजेक्ट पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की अनुमति से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए थे। आरोप है कि विभाग ने इन सूचनाओं को सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया और कुछ मामलों में अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई।

आरटीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप

सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे ने आरोप लगाया है कि चीता प्रोजेक्ट के प्रभारी उत्तम शर्मा ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन किया है। उनके अनुसार, उन्होंने स्वयं को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय अधिकारी घोषित कर नियमों के विपरीत आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता का कहना है कि सूचना का अधिकार कानून लागू होने के दो दशक बाद भी इस तरह की अनियमितताएं चिंताजनक हैं। उन्होंने राज्य सूचना आयोग से मामले की विभागीय जांच कराने, जुर्माना लगाने और क्षतिपूर्ति देने की मांग की है। अब आयोग पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है।

ट्रेन में छूटा 70 हजार का लैपटॉप, RPF ने लौटाया बैग

भोपाल. दोपहर मेट्रो। ट्रेन यात्रा के दौरान खंडवा से भोपाल जा रहे खरगोन जिले के नागझिरी निवासी 20 वर्षीय हर्ष राठौर का करीब 70 हजार रुपये कीमत का लैपटॉप, चार्जर और जरूरी दस्तावेजों से भरा बैग ट्रेन में छूट गया। अधिक भीड़ होने के कारण हर्ष ने दूसरी ट्रेन से सफर करने का फैसला किया और जल्दबाजी में सामान्य कोच में बैग भूल गए। सूचना मिलते ही हरदा आरपीएफ की टीम ने ट्रेन संख्या 17020 के हरदा स्टेशन पहुंचते ही तलाशी अभियान चलाया और बैग बरामद कर लिया। सत्यापन के बाद बैग सुरक्षित यात्री को सौंप दिया गया।

सीएम ने गोदड़ी पर बैठकर किया भोजन

जनजातीय समाज के प्रति आत्मीय जुड़ाव और उनकी संस्कृति के सम्मान की झलक झाबुआ जिले के थांदला में देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश स्तरीय स्व-सहायता समूहों के क्षमतावर्धन एवं ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समुदाय के सदस्य बसंत सिंह बामनिया के घर पहुंचकर उनके परिवार के साथ समय बिताया और जनजातीय जीवनशैली को करीब से जाना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परिवार के सदस्यों से सहज संवाद किया और उनके सुख-दुख की जानकारी ली। इस अवसर पर जनजातीय समाज की बहनों ने सावन मास और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने बहनों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सम्मान और सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदमः झाबुआ में महिला शक्ति का महाकुंभ

सीएम ने स्व-सहायता समूहों को बांटा 300 करोड़ का लोन, बोले- बहनों की ताकत से आगे बढ़ रहा मप्र

झाबुआ, दोपहर मेट्रो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण अब केवल सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। स्व-सहायता समूहों से जुड़ी बहनें कृषि, पशुपालन, बैंकिंग और उद्यमिता के क्षेत्र में नई पहचान बना रही हैं। उनकी मेहनत से परिवारों में समृद्धि आ रही है और प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री झाबुआ जिले के थांदला में आयोजित स्व-सहायता समूहों के क्षमतावर्धन एवं ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहनों की शक्ति और आशीर्वाद से मध्यप्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों से जुड़ी बहनों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। इससे लाखों महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वारा 196 दीदी कैफे संचालित किए जा रहे हैं, जबकि झाबुआ जिले में भी चार कैफे चल रहे हैं। इसके अलावा 85 आजीविका पुस्तकालयों की जिम्मेदारी भी समूहों की बहनों के पास है।

कृषि से ड्रोन तक महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की महिलाएं खेती से लेकर आधुनिक तकनीक तक अपनी क्षमता साबित कर रही हैं। ड्रोन दीदी खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं, वहीं कृषि सखी, पशुपालन दीदी और बैंक सखी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने इस वर्ष देश में सबसे अधिक 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया है, जिसमें महिला समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश में 89 ड्रोन दीदियां सहित हजारों महिलाएं जैविक खेती, पशुपालन, मछली पालन और व्यावसायिक उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने झाबुआ जिले को 174.64 करोड़ रुपए के 29 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 109.17 करोड़ रुपए के 28 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए और मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया।

रोजगार के लिए अब पलायन नहीं करना पड़ेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग और एमएसएमई के माध्यम से रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर क्षेत्र में संचार क्षेत्र की नई इकाई स्थापित होगी, जिससे करीब 14 हजार रोजगार के अवसर बनेंगे। वहीं धार जिले में स्थापित होने वाले पीएम मित्र पार्क से तीन लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि झाबुआ, धार और आलीराजपुर जैसे जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को अब रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आने वाले समय में बड़े उद्योग यहां स्थापित होंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होंगे।

यात्री परिवहन विजन समिट-2026

मप्र में बदलने जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा, कई एक्सपर्ट एक साथ करेंगे अहम मंथन

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा बदलने जा रहे हैं। यह दिशा एक ओर जहां आम लोगों की जिंदगी बेहतर करेगी, वहीं सरकारी सिस्टम को भी लाभ पहुंचाएगी। दरअसल, 11-12 सितंबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यात्री परिवहन विजन समिट-2026 का आयोजन होगा। यह समिट मध्यप्रदेश से सार्वजनिक परिवहन के नए भविष्य का निर्माण करेगी। इस समिट में कई विशेषज्ञ परिवहन संबंधित विषयों पर मंथन करेंगे।

मुख्यमंत्री समिट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और मध्य प्रदेश यात्री मोबिलिटी विजन 2030 पर संबोधन देंगे। वे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना और यात्री परिवहन को सुदृढ़ करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका पर विचार रखेंगे। इसके साथ-साथ सीएम डॉ. मोहन उद्योग जगत के प्रतिनिधियों-निवेशकों और नीति-निर्माताओं के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान वे शिखर सम्मेलन स्मारिका-ज्ञान प्रकाशन का विमोचन भी करेंगे। बता दें, यह समिट वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नीति-निर्माताओं, शहरी परिवहन विशेषज्ञों, परिवहन प्राधिकरणों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, ओईएम, वित्तीय संस्थानों और उद्योग जगत के अग्रणी नेताओं को एक मंच पर लाएगी। यह समिट नवाचार, डिजिटल तकनीकों और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन में परिवर्तन को नई दिशा देगी। गौरतलब है कि यात्री परिवहन विजन समिट 2026% भारत का प्रमुख राष्ट्रीय मंच है।

समिट में इन विषयों पर होगी चर्चा

- **एमपी मोबिलिटी विजन 2030:** बस संचालन एवं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में सार्वजनिक-निजी भागीदारी
- **भविष्य के लिए तैयार परिवहन अधोसंरचना:** पीपीपी के माध्यम से निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना
- **डेटा आधारित निर्णय:** इंट्रासिटी एवं इंटरसिटी बस मार्गों और संचालन की योजनाआधारित एनालिटिक्स सहित)
- वित्तीय रूप से टिकाऊ सार्वजनिक बस संचालन के निर्माण की रणनीतियां
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में जनसुरक्षा, विश्वसनीयता एवं सुविधा
- **हरित मोबिलिटी:** स्वच्छ ईंधन एवं भविष्य के लिए तैयार गाड़ियों का काफिला
- एकीकृत टिकटिंग एवं स्वचालित किराया संग्रहण के माध्यम से निर्बाध यात्राओं को सक्षम बनाना

क्या-क्या होगा दो दिन

यात्री परिवहन विजन समिट-2026 के पहले दिन उद्घाटन सत्र, मुख्य वक्तव्य, उच्चस्तरीय पैनल चर्चाएं, उद्योग प्रदर्शनी, नेटवर्किंग सत्र तथा ज्ञान-साझाकरण संबंधी संवाद आयोजित किए जाएंगे। इनमें नीति, नवाचार, निवेश और यात्री परिवहन के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जबकि, दूसरे दिन प्रतिनिधियों के लिए उज्जैन सांस्कृतिक-विरासत भ्रमण आयोजित किया जाएगा। इसमें श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल दर्शन शामिल होगा। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के साथ-साथ राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा।

नर्मदापुरम में ब्लैकलिस्टेड वेयरहाउस सील

28 करोड़ रुपए की मूंग बनी 'मिट्टी' सरकारी महकमे में मच गया हड़कंप

- गोपनीय शिकायत के बाद छापे में खुली करोड़ों की धांधली
- ब्लैकलिस्ट वेयरहाउस को दोबारा अनुमति मिलने पर भी उठे सवाल

नर्मदापुरम, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सरकारी मूंग के भंडारण में करोड़ों की कथित अनियमितता का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। माखननगर स्थित कनकधारा वेयरहाउस में रखी करीब 31,298 क्विंटल सरकारी मूंग, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 28.14 करोड़ रुपये बताई जा रही है, उसकी जांच में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच दल को कई बोरियों में मूंग की जगह मिट्टी, कंकड़-पत्थर और निम्न गुणवत्ता का सामग्री मिली। प्रारंभिक जांच और लैब रिपोर्ट में गुणवत्ता संबंधी गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने वेयरहाउस को तत्काल सील कर दिया है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा को मिली गोपनीय शिकायत के आधार पर एसडीएम देवेंद्र सिंह, जिला आपूर्ति अधिकारी और उप संचालक कृषि की संयुक्त टीम ने कनकधारा वेयरहाउस पर औचक निरीक्षण किया। रिकॉर्ड में दर्ज 23 स्टैक्स का रैंडम परीक्षण किया गया, जिसमें कई बोरियों में निर्धारित गुणवत्ता के विपरीत सामग्री मिली। अधिकारियों के अनुसार, सरकारी मानकों के अनुरूप एफएक्यू गुणवत्ता की मूंग के स्थान पर निम्न गुणवत्ता का अनाज और अन्य सामग्री भरी गई थी।

पहले ब्लैकलिस्ट, फिर कैसे मिली अनुमति?

जांच के दौरान सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठा कि जिस कनकधारा वेयरहाउस को एक वर्ष पहले अनियमितताओं के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया था, उसे दोबारा सरकारी भंडारण की अनुमति किस आधार पर दी गई। आरोप है कि वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक वासुदेव डवडे, जो पिछली जांच प्रक्रिया का भी हिस्सा थे, उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में है। इस पहलू को लेकर प्रशासन अलग से जांच कर रहा है।

तीन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज| मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला विपणन अधिकारी अनिल जैन की शिकायत पर माखननगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने वेयरहाउस संचालक तारेश पुरोहित, तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्याम होसले और जिला प्रबंधक वासुदेव डवडे के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

जांच तेज, आरोपियों की तलाश जारी

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस बीच मुख्य आरोपी वेयरहाउस संचालक तारेश पुरोहित के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी भी सामने आई है। नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यदि जांच में अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बिना सरकारी मदद शिक्षक संगठन ने बांटे 4.33 करोड़

दिवंगत कर्मचारी के परिजन की मदद के लिए हर मेंबर ने दिए 170 रुपए

15 दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को दी गई 27.50 लाख राहत

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के नाम से बनाए गए एक संगठन ने दिवंगत शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को बगैर किसी सरकारी मदद के चार करोड़ 33 लाख रुपए की मदद पहुंचाई है।

एक साल पहले शुरू की गई इस मानवीय पहल में अब तक 15 दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को 27.50 लाख रुपए की राहत देने का काम किया है। सामाजिक संवेदना के जरिए शिक्षकों की टीम अपने साथी शिक्षकों को आर्थिक संबल देने का काम कर रही है।

PMUMS शिक्षक संगठन ने एक साल पहले यह तय किया कि यदि शिक्षा विभाग अथवा ट्राइबल विभाग में कार्यरत कोई कर्मचारी सेवाकाल के दौरान किसी कारणवश दिवंगत हो जाता है, तो संगठन के सभी पंजीकृत सदस्य मिलकर उनके परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं।

PMUMS संगठन के भोपाल संभाग अध्यक्ष ऋतुराज तिवारी ने बताया कि इस व्यवस्था में हर पंजीकृत सदस्य मात्र 45 से 50 तक की न्यूनतम राशि सीधे दिवंगत कर्मचारी के नामांकित (नॉमिनी) परिवारजन के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करता है।

इस प्रकार एक परिवार को लगभग 26 से 27 लाख तक का सहयोग प्राप्त हो जाता है। सहयोग की यह प्रक्रिया हर माह की 5 से 20 तारीख के मध्य संचालित की जाती है तथा संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है।

नहीं हुई कोई फंडिंग

बृजेश कुमार असाटी, सह-संस्थापक कर्मचारी कल्याण कोष, मध्य प्रदेश ने बताया कि प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संगठन (पीएमयूएमएस) के नाम से बने इस संगठन की खास बात यह है कि हम मामूली राशि लेकर लोगों को मदद करते हैं। इसके लिए कोई फंडिंग नहीं की जाती है। जुलाई में अब तक चार शिक्षकों के परिवारों को एक करोड़ 8 लाख 20 हजार रुपए की मदद की है। इसके लिए हमने चार क्यूआर कोड बनाए और संगठन के सभी सदस्यों को बराबर संख्या में क्यूआर कोड भेजकर 170 रुपए की मदद करने के लिए कहा।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने सड़क सुरक्षा प्रबंधन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण

भोपाल। सड़क सुरक्षा प्रबंधन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस परिवहन शोध संस्थान (पीटीआरआई) में आयोजित किया गया। इसमें सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात परिवहन की नई तकनीकों से परिचय, वाहन दुर्घटनाओं में पीड़ितों को शासकीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता, कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने संबंधी जानकारी दी गयी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मोहम्मद शाहिद अबसार के निर्देशानुसार यह प्रशिक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से आरक्षक स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों को दिया गया।

राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट में 5.67 करोड़ वोटर्स, SIR के बाद 5.39 करोड़ थे

भोपाल, दोपहर मेट्रो

चुनाव आयोग द्वारा कराई गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजनकी प्रोसेस के बाद एमपी में मतदाताओं की संख्या में 27.40 लाख की वृद्धि हुई है। मतदाताओं की संख्या में यह बढ़ोतरी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई गई मतदाता सूची की रिपोर्ट में सामने आई है। चूंकि अगले साल एमपी में नगर निगम, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई गई मतदाता सूची चर्चा में है। इस मतदाता सूची में शहरी के मुकाबले ग्रामीण मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 2027 में कराए जाने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में तैयार वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे। इसलिए इस मतदाता सूची में आने वाले समय में बदलाव होना भी तय है।

चार करोड़ से अधिक मतदाता ग्रामीणों में

राज्य निर्वाचन आयोग से तैयार कराई गई मतदाता सूची के बाद यह बात सामने आई है कि प्रदेश में कुल 5 करोड़ 67 लाख 21 हजार 353 मतदाता है। इसमें चार करोड़ 6 लाख 70 हजार मतदाता ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र के वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 60 लाख 50 हजार 984 है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच एसआईआर की कार्यवाही कराई थी।

मिट्ठू के बिछड़ने से दुखी ग्वालियर का परिवार

दादी-पोती ने छोड़ा खाना, पालतू तोते पर 50 हजार रुपए का इनाम

ग्वालियर। ग्वालियर के अलकापुरी-कलेक्ट्रेट रोड स्थित एनजी ग्रांड में रहने वाले अनिल ओझा का परिवार इन दिनों अपने पालतू तोते शकुंतला उर्फ मिट्ठू की तलाश में जुटा है। करीब तीन दिन पहले घर से उड़ जाने के बाद परिवार लगातार उसकी खोज कर रहा है। मिट्ठू को सुरक्षित घर वापस लाने वाले व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है। अनिल ओझा का कहना है कि उनके लिए इनाम की राशि से ज्यादा मायने मिट्ठू का सकुशल घर लौटना रखता है। खोज के लिए पोस्टर चिपकाए गए और अनाउंसमेंट भी कराई जा रही है।

अनिल ओझा के मुताबिक, करीब एक वर्ष पहले मिट्ठू उनके घर आया था। समय के साथ वह परिवार के हर सदस्य के बेहद करीब हो गया। उसे कभी पिंजरे में बंद नहीं रखा गया। वह पूरे घर में स्वतंत्र रूप से घूमता था और परिवार के लोगों की आवाज सुनते ही उनके हाथ या कंधे पर आकर बैठ जाता था। इसी वजह से सभी का उससे गहरा भावनात्मक लगाव हो गया था। परिवार के अनुसार, सोमवार को घर की एक खिड़की खुली रह गई थी। इसी दौरान मिट्ठू बाहर उड़ गया। शुरुआत में सभी को उम्मीद थी कि वह कुछ देर बाद वापस लौट आएगा, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी वह घर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी।

मेट्रो एंकर

उनशामुक्ति अभियान ने रचा विश्व रिकॉर्ड!

बालाघाट पुलिस की पहल को मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश पुलिस का ÷नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0÷ अभियान अब देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन में चल रहे इस जनजागरूकता अभियान के तहत बालाघाट पुलिस ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन ने विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता देते हुए %सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस% से सम्मानित किया है।

बालाघाट पुलिस ने नशामुक्ति के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जिले के 1,204 विद्यालयों में एक साथ सामूहिक शपथ कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान करीब 1 लाख 25 हजार विद्यार्थियों ने एक मिनट में नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। वहीं, 5 लाख से अधिक नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से अभियान से जुड़कर इस जनआंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता ने इस पहल को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई।

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस अभियान को केवल रिकॉर्ड संख्या के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में नशे के खिलाफ जनजागरूकता फैलाने की प्रभावी पहल के रूप में भी सराहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून के बल पर नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसमें विद्यार्थियों, युवाओं, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

प्रदेशभर में जारी है अभियान

नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत मध्य प्रदेश पुलिस लगातार नशामुक्ति शपथ, जागरूकता रैलियां, संवाद कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक गतिविधियां और स्कूल-कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

पहले भी बन चुके हैं कई विश्व रिकॉर्ड

इस अभियान के तहत इससे पहले भी प्रदेश के कई जिलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने 1 लाख 75 हजार 451 नागरिकों को एक साथ ई-शपथ दिलाकर और 8,534 लोगों की मानव श्रृंखला बनाकर दो विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए थे। वहीं, बड़वानी पुलिस को 16,700 ड्राइंग शीट्स पर नशामुक्ति संदेश लिखवाने के लिए सम्मान मिला, जबकि बुरहानपुर में 32 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से नशामुक्ति संदेश लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।

युवा जवाबदेही मांगते हैं

किसी राष्ट्र का भविष्य उसकी संसद में नहीं, उसकी कक्षाओं में लिखा जाता है। संसद कानून बना सकती है, सरकार नीतियां तय कर सकती है, लेकिन किसी देश की वास्तविक दिशा उसके युवाओं की आकांक्षाएं निर्धारित करती हैं। जब वही युवा सड़कों पर उतरकर शिक्षा में जवाबदेही की मांग करें, तो इसे केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए चेतावनी और अवसर-दोनों के रूप में देखा जाना चाहिए। दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश के अनेक शहरों तक पहुंचे छात्रों की आवाज किसी एक परीक्षा, एक भर्ती या एक संस्थान के खिलाफ नहीं थी। उनकी मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, जहां मेहनत का मूल्य हो, परीक्षा की विश्वसनीयता पर संदेह न हो और किसी छात्र का भविष्य पेपर लीक, तकनीकी अव्यवस्था या प्रशासनिक लापरवाही का शिकार न बने। यह मांग असाधारण नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। करोड़ों परिवारों के लिए शिक्षा गरीबी से बाहर निकलने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। किसी किसान, मजदूर या निम्न मध्यमवर्गीय परिवार का छात्र वर्षों तक तैयारी करता है, परिवार अपनी जमा-पूंजी खर्च करता है और एक परीक्षा के भरोसे भविष्य के सपने बुनता है। ऐसे में जब प्रश्नपत्र लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द होती हैं या पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तो केवल परीक्षा नहीं टूटतीविश्वास भी टूटता है। हालिया आंदोलन के बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में बदलाव, फास्ट-ट्रैक अदालतों और अन्य सुधारात्मक कदमों का आश्वासन दिया है। ये घोषणाएं स्वागत योग्य हैं, लेकिन किसी भी सुधार का वास्तविक मूल्यांकन उसके क्रियान्वयन से होगा। युवाओं को अब वादों से अधिक परिणाम चाहिए। उन्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें ईमानदार मेहनत को किसी संगठित भ्रष्टाचार के सामने हार न माननी पड़े। इस पूरे घटनाक्रम का एक गहरा मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। आज की पीढ़ी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, डिजिटल रैंकिंग और निरंतर प्रदर्शन के दबाव में जी रही है। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि सफलता का रास्ता मेहनत से होकर जाता है। लेकिन जब व्यवस्था ही निष्पक्ष न दिखे, तो निराशा केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आत्मविश्वास और भविष्य की उम्मीद को भी प्रभावित करती है।

खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट, स्वास्थ्य और समाज पर बढ़ता गंभीर संकट

ऋतुपर्ण दवे
स्तंभकार

'जैसा अन्न, वैसा मन'—भारतीय संस्कृति का यह प्राचीन कथन केवल आध्यात्मिक संदेश नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज की बुनियादी शर्त भी है। दुर्भाग्य से आज यही अन्न, दूध, मसाले, तेल, मिठाइयाँ और दैनिक उपयोग के अनेक खाद्य पदार्थ मिलावट की गिरफ्त में हैं। यह समस्या अब केवल उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी तक सीमित नहीं रही, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक नैतिकता के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। हर त्योहार, हर शादी-ब्याह के मौसम और यहां तक कि रोजमर्रा के बाजार में भी मिलावटी खाद्य पदार्थों की खबरें आम हो गई हैं। यह स्थिति बताती है कि भोजन की शुद्धता का प्रश्न अब व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट का अर्थ केवल किसी वस्तु में सस्ता पदार्थ मिला देना नहीं है। कई बार इसमें ऐसे रसायनों और औद्योगिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो मानव शरीर के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। दूध में यूरिया और डिटर्जेंट, घी में वनस्पति तेल, हल्दी में लेड क्रोमेट, मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, धनिया में लकड़ी का बुरादा, शहद में शुगर सिरप, सरसों के तेल में सस्ते तेलों की मिलावट और मिठाइयों में कृत्रिम रंग—ये सब केवल मुनाफाखोरी के उदाहरण नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हैं। चिंताजनक बात यह है कि मिलावट अब छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं रह गई है। संगठित स्तर पर भी नकली और मिलावटी उत्पादों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। पैकेजिंग इतनी आकर्षक होती है कि आम उपभोक्ता असली और नकली में अंतर नहीं कर पाता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अनियंत्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं ने भी इस समस्या को नया आयाम दिया है। कई बार प्रतिष्ठित ब्रांडों की नकली पैकिंग में निम्न गुणवत्ता के उत्पाद बाजार में पहुंच जाते हैं।

स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव बेहद गंभीर हैं। मिलावटी भोजन से केवल पेट खराब होने जैसी सामान्य समस्याएं नहीं होतीं, बल्कि लंबे समय तक ऐसे पदार्थों का सेवन करने से लीवर, किडनी, हृदय और तंत्रिका तंत्र पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। कैंसर, हार्मोनल असंतुलन, एलर्जी, बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा, महिलाओं में गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं और बुजुर्गों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसे खतरे भी इससे जुड़े हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि असुरक्षित खाद्य पदार्थ अनेक गैर-संचारी रोगों की बड़ी वजह बन रहे हैं।

सबसे अधिक चिंता बच्चों की है। उनका शरीर विकास की अवस्था में होता है और थोड़ी-सी भी विषाक्तता का प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। स्कूलों के आसपास बिकने वाले रंगीन पेय, सस्ती मिठाइयां, खुले चिप्स, नकली आइसक्रीम और कृत्रिम रंगों से बने खाद्य पदार्थ बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। विडंबना यह है कि जिन अभिभावकों को इन खतरों की जानकारी भी होती है, वे कई बार कीमत कम होने या सुविधा के कारण ऐसे उत्पाद खरीद लेते हैं। मिलावट का आर्थिक पक्ष भी कम गंभीर नहीं है। उपभोक्ता अपनी मेहनत की कमाई से शुद्ध वस्तु खरीदने का विश्वास लेकर बाजार जाता है, लेकिन उसे घटिया या नकली उत्पाद मिलता है। इससे ईमानदार व्यापारियों को भी नुकसान होता है, क्योंकि मिलावट करने वाले कम कीमत पर बाजार में प्रतिस्पर्धा पैदा कर देते हैं। धीरे-धीरे गुणवत्ता का महत्व घटने लगता है और मुनाफाखोरी का मॉडल मजबूत होता जाता है। इससे बाजार की विश्वसनीयता प्रभावित होती है और उपभोक्ता का भरोसा कमजोर पड़ता है।

भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए कानूनों और संस्थाओं की कमी नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। समय-समय पर जांच अभियान भी चलाए जाते हैं और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन यह भी सच है कि अधिकांश कार्रवाई त्योहारों के दौरान ही अधिक दिखाई देती है। वर्षभर नियमित निरीक्षण, पर्याप्त प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षित खाद्य निरीक्षक और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया अभी भी अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच सकी हैं। कई मामलों में जांच रिपोर्ट आने में इतना समय लग जाता है कि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का असर कम हो जाता है।

एक बड़ी चुनौती जागरूकता की भी है। उपभोक्ता यदि खरीदते समय लेबल, निर्माण तिथि, गुणवत्ता प्रमाणन और पैकेजिंग की जांच करें तो कई स्तर पर धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। खुले में बिकने वाले अत्यधिक सस्ते खाद्य पदार्थों से बचना, विश्वसनीय दुकानों से खरीदारी करना और संदिग्ध उत्पादों की शिकायत करना भी नागरिक जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए। आज कई सरल घरेलू परीक्षणों से दूध, मसालों और अन्य खाद्य पदार्थों में प्रारंभिक स्तर की मिलावट का पता लगाया जा सकता है। यदि इनकी जानकारी व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचे तो मिलावटखोरों के लिए बाजार सीमित हो सकता है।

भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और राष्ट्र की उत्पादक क्षमता का आधार है। यदि हमारी थाली ही असुरक्षित होगी तो स्वस्थ भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। मिलावट के खिलाफ लड़ाई किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का साझा अभियान बननी चाहिए। जिस दिन मिलावट करने वाले यह समझ जाएंगे कि कानून भी कठोर है, समाज भी जागरूक है और उपभोक्ता भी सतर्क है, उसी दिन इस समस्या पर वास्तविक अंकुश लगना शुरू होगा। आखिरकार, शुद्ध भोजन केवल उपभोक्ता का अधिकार नहीं, बल्कि सभ्य और जिम्मेदार समाज की पहचान भी है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

लगातार तप रही है धरती... बढ़ती गर्मी और मानव जीवन पर मंडराता खतरा

सुनील कुमार महला
स्तंभकार

धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही मानव सभ्यता के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है, जिसे अब भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की चुनौती कहा जाना चाहिए। कभी गर्मी के मौसम में लू चलना एक सामान्य प्राकृतिक घटना मानी जाती थी, लेकिन अब अप्रैल से जून ही नहीं, जुलाई और अगस्त तक भी कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कहीं अधिक बना रहता है। बारिश का समय बदल रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं और समुद्र का स्तर लगातार ऊपर उठ रहा है। यह सब किसी विज्ञान कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे समय की कठोर सच्चाई है।

दुनिया के अनेक वैज्ञानिक वर्षों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो पृथ्वी पर जीवन के लिए परिस्थितियां लगातार कठिन होती जाएंगी। आज स्थिति यह है कि दुनिया के कई शहर हर वर्ष नए तापमान रिकॉर्ड बना रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर भारत से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक भीषण गर्मी और असामान्य मौसम अब सामान्य अनुभव बनते जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि आखिर धरती इतनी तेजी से क्यों तप रही है? इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियां हैं। औद्योगिकीकरण, अंधाधुंध शहरीकरण, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गैसें पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। परिणामस्वरूप धरती का तापमान धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। विकास की अंधी दौड़ में हमने प्रकृति से जितना लिया, उसके बदले उसे लौटाने की गंभीर कोशिश कभी नहीं की। बढ़ती गर्मी का सबसे बड़ा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लू लगने, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, हृदय रोग और सांस संबंधी बीमारियों के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बाहर काम करने वाले श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। खेतों में काम करने वाले किसान, निर्माण स्थलों के मजदूर, ट्रैफिक पुलिस और डिलीवरी कर्मियों के लिए दोपहर का समय जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष जैसा बनता जा रहा है। कई शहरों में गर्मी के कारण मृत्यु के मामले अब नियमित रूप से सामने आने लगे हैं।

केवल स्वास्थ्य ही नहीं, अर्थव्यवस्था भी इस संकट की चपेट में है। अत्यधिक तापमान से कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। गेहूं, धान, दालें और बागवानी फसलों की उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पानी की मांग बढ़ रही है, जबकि भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है क्योंकि एयर कंडीशनर और कूलर का उपयोग बढ़ रहा है। दूसरी ओर, बिजली उत्पादन पर भी दबाव बढ़ता है और कई क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित होती है। इसका सीधा असर उद्योगों, व्यापार और आम जनजीवन पर पड़ता है। बढ़ती गर्मी ने शहरों की योजना पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कंक्रीट के जंगलों में हरियाली लगातार कम हो रही है। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और डामर की सतह दिनभर गर्मी सोखती हैं और रात में उसे छोड़ती रहती हैं। परिणामस्वरूप शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक हो जाता है। इसे 'अर्बन हीट आइलैंड' प्रभाव कहा जाता है। यदि शहरों में पर्याप्त पेड़, खुले मैदान, जलाशय और हरित क्षेत्र न बचाए गए तो भविष्य में महानगर रहने लायक नहीं रह जाएंगे। इस संकट का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है, जिनका प्रदूषण फैलाने में सबसे कम योगदान है। गरीब, किसान, आदिवासी, मछुआरे और निम्न आय वर्ग जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जिनके पास वातानुकूलित घर, पर्याप्त पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वे किसी तरह गर्मी से बच सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग आज भी ऐसी सुविधाओं से दूर हैं। जलवायु परिवर्तन सामाजिक असमानता को और गहरा कर रहा है।

प्रकृति भी इस बदलाव का भारी मूल्य चुका रही है। जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। अनेक पक्षियों और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। नदियों का जलस्तर घट रहा है, झीलें सिकुड़ रही हैं और जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। समुद्री पारिस्थितिकी भी प्रभावित हो रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में अनेक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती हैं। विडंबना यह है कि हम इस संकट की गंभीरता को जानते हुए भी अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। आज भी अनियोजित निर्माण, पेड़ों की कटाई, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता जारी है। पर्यावरण संरक्षण की बातें अक्सर सम्मेलनों और घोषणाओं तक सीमित रह जाती हैं। जलवायु परिवर्तन केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है; यह प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है।

भारत जैसे विशाल देश के सामने चुनौती और अवसर दोनों हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा दक्ष भवन, सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे उपायों को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना होगा। शहरों में हरित क्षेत्रों को बढ़ाना, जलाशयों का संरक्षण और निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन करना समय की मांग है। किसानों को भी बदलते मौसम के अनुरूप खेती की नई तकनीकों और कम पानी वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

धरती का तापमान केवल मौसम का आंकड़ा नहीं है; यह मानव सभ्यता के भविष्य का संकेतक है। यदि आज भी हमने प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करने की दिशा में गंभीर कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियां हमें उस पीढ़ी के रूप में याद करेंगी जिसने विकास के नाम पर अपने ही भविष्य को संकट में डाल दिया। समय अभी पूरी तरह हाथ से नहीं निकला है, लेकिन चेतावनी की घंटी लगातार बज रही है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम उसे सुनने और उसके अनुसार बदलने को तैयार हैं? क्योंकि यदि धरती यूं ही तपती रही, तो सबसे बड़ा संकट किसी देश, किसी सरकार या किसी अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि स्वयं मानव जीवन पर होगा।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अपडेट

सिर्फ धूल नहीं, बारिश से भी हो सकती है अस्थमा मरीजों को परेशानी

बारिश के मौसम में गर्मी से राहत तो मिल जाती है, लेकिन वहीं अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बारिश का मौसम किसी चुनौती से कम नहीं होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में तकरीबन 26 करोड़ अस्थमा के पेशेंट हैं। रिपोर्ट के अनुसार मॉनसून में अस्थमा के मरीजों की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बरसात के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है। बढ़ी हुई नमी और ठंडी हवा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूजन पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा बारिश की वजह से जगह-जगह जमा पानी, पॉलेन ग्रेन और फंगल स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं, जिससे अस्थमा के मरीजों को एलर्जी की समस्या शुरू हो सकती है।

टेक्सास के ओकबेंड मेडिकल सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार बारिश के कारण अस्थमा की समस्या बढ़ने के पीछे बढ़ी हुई नमी, पोलन ग्रेन और फफूंदी के अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं। मॉनसून के मौसम में ज्यादातर लोगों का समय घर के अंदर बीतता है। घर के अंदर भी धूल के कण, पालतू जानवरों के शरीर की रूसी और घर के अंदर अपने आप पनपने वाले फफूंदी अस्थमा के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। सांस लेने वाली नली मौसम के बदलने की वजह से और ज्यादा सेंसेटिव हो सकती हैं, जिससे अस्थमा के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है।

माना जाता है कि बारिश में हवा साफ होने के साथ-साथ पराग कणों की मात्रा को भी कम कर देती है। लेकिन जर्नल ऑफ एप्लाइड मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार थंडरस्टॉर्म के कारण अस्थमा पेशेंट्स की तकलीफ और बढ़ सकती है। अस्थमा एंड एलर्जी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार मॉनसून में अस्थमा मरीजों को 3 सबसे महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक ठंडे पानी का इस्तेमाल करने या ठंडी खाने-पीने की चीजों के सेवन से अस्थमा की परेशानी बढ़ सकती है। सर्दी-जुकाम होना, खांसी होना, थकावट महसूस होना, सीने में भारीपन महसूस होना। ऐसे लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इन लक्षणों के बाद ही अस्थमा की समस्या ट्रिगर करती है। अपनी दवाओं और इनहेलर का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

बारिश के मौसम में अस्थमा के मरीजों के साथ-साथ जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है, बच्चों और बुजुर्गों को भी सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि अस्थमा या एलर्जी की समस्या होने पर इस मौसम में परेशानी बढ़ सकती है। वहीं अगर एलर्जी या अस्थमा की परेशानी कम ना हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

निशाना

अश्क में नहाया देर तक..!

धर्मराज देशराज

अश्क में जब मैं नहाया देर तक
तब कहीं वो मुस्कुराया देर तक।
वो बदल जायेगा इस उम्मीद पर
आईना उसको दिखाया देर तक।
ग़म छुपाने का जतन यूँ भी किया
बेसबब ही मुस्कुराया देर तक।
रात सारी कट गयी बेकार ही
ख्वाब भी उसका न आया देर तक।
मेरे रोने पर हँसा है यार खुद
ओर मुझको भी हँसाया देर तक।
कद्र जिसने वक्त की यारो न की
वक्त ने उसको रुलाया देर तक।
चाँद का दीदार छत पर क्या हुआ
दिल हमारा कसमसाया देर तक।
धूप इतनी दर्दो- ग़म की थी 'धरम'
छुप गया अपना ही साया देर तक

इनोवेशन

कश्मीरी इनोवेटर्स ने बनाया पहला ट्राई-हाइब्रिड स्कूटर, सोलर-इलेक्ट्रिक-पेट्रोल तीनों से चलेगा

कश्मीर के दो इनोवेटर्स ने भारत का पहला ट्राई-हाइब्रिड थ्री-व्हीलर स्कूटर पेश किया है, जिसका नाम 'शी' (स्वाश्व) रखा गया है। इस स्कूटर की सबसे खास बात है कि यह सोलर एनर्जी, बिजली और पेट्रोल तीनों से चलता है। इस स्कूटर को बनाने का मकसद पारंपरिक चार्जिंग सिस्टम और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करना है। इस स्कूटर को बनाने वाले कश्मीर के दो लोगों के नाम बिलाल अहमद मीर और बिनिश गुलज़ार हैं। इन दोनों ने इसे अपनी कंपनी बिलाल्स इनोवेटिव सोलर ऑटोमोबाइल के तहत बनाया है। मीर ने बताया कि वो पिछले 15 साल से ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं और इससे पहले वो भारत की पहली हाई-टेक सोलर कार बना चुके हैं, जिसके लिए उन्हें छह पेटेंट भी मिले हैं।

इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी पेटेंट टेक्नोलॉजी Range Elevated Electric Scooter है। मीर का दावा है कि यह टेक्नोलॉजी किसी भी व्हीकल में लगाई जा सकती है और यह पूरी तरह बाहरी चार्जिंग पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि सोलर एनर्जी से बैटरी अपने आप चार्ज होती रहती है।

श्रीनगर-जम्मू के बीच टनल में सफर के दौरान या खराब मौसम में अक्सर सूरज की रोशनी काफी कम होती है.। ऐसे परिस्थिति में पेट्रोल इंजन अपने आप ऑन हो जाता है और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को चार्ज करता रहता है, जिससे स्कूटर की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। मीर का कहना है कि इस इनोवेशन को पेटेंट मिल चुका है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है।

शी को सामान्य इंसानों के साथ-साथ दिव्यांगों के लिए भी बनाया गया है। इसमें एक डिटैचेबल और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सीट दी गई है, जिसे स्विच के ज़रिए ऊपर-नीचे किया जा सकता है। मीर ने बताया कि सीट हटाने पर यह सामान्य बाइक बन जाती है, जबकि दिव्यांग राइडर के लिए सीट पूरी तरह इलेक्ट्रिक तरीके से ऊपर-नीचे होकर चढ़ने-उतरने में आसानी देती है। इस स्कूटर में करीब 200 किलोग्राम तक सामान लेकर जाने की क्षमता वाला स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है। इससे यह फूड डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स के लिए भी उपयोगी हो सकता है।

वायरल कंटेंट

रेल अफसरों का आलीशान इंस्पेक्शन कोच, लग्जरी रिसॉर्ट जैसी सुविधाएं

आपने रेलवे में जनरल से लेकर स्लीपर, 3AC, 2AC, 1AC और यहां तक कि एसी चेयरकार भी देखा होगा। बीते दिनों एक सैलून कोच का भी वीडियो भी आया था जिसे एक ग्राहक ने 3 लाख से अधिक की राशि देकर बुक करवाया था। मगर अब एक शख्स ने रेलवे के अधिकारियों के लिए बनाए गए इंस्पेक्शन कैरेज का जो वीडियो डाला है, वह भी कम लग्जरी नहीं है और इंटरनेट का ध्यान खींच रहा है।

निरीक्षण कक्ष एक प्रकार का स्पेशल रेल कोच होता है। जिसका इस्तेमाल अधिकारी और इंजीनियर सेफ्टी ऑडिट, ट्रैक मॉनिटरिंग और नेटवर्क निगरानी के लिए पटरियों पर यात्रा के दौरान करते हैं। ये बोगी आम लोकोमोटिव द्वारा खींचे जाने वाले इंस्पेक्शन डिब्बों से लेकर मॉडर्न और ऑटोमैटिक रेल एयर कंडीशन्ड कारों की तरह होती है। इस बोगी को सैलून कोच भी कहते हैं। जिसके अंदर रेलवे के DRM से लेकर तमाम सीनीयर अधिकारी सफर करते है। ट्रेन की एंट्री पर किचन दिखता है। जिसके बारे बंदा बताता है कि यहां कुक होता है, जो अधिकारियों के लिए खाना पकाता है। एंट्री से पहले एक बाथरूम भी दिखता है। जिसके बाद स्टाफ के लिए अलग बर्थ वाला केबिन भी होता है।

वीडियो में इसके आगे लंच रूम दिखाता है, जो फुली एसी होता है। वहां टीवी से लेकर लंच टेबल, सोफा और आरामदायक लकड़ी की कुर्सियां भी रखी होती है। इसके बाद वीडियो बना रहा शख्स अधिकारियों के आराम के लिए बना कमरा भी दिखाता है, जिसमें डबल बेड होता है।

वीडियो के मुताबिक सेलून में लगभग 1 बड़ा और 1 छोटा कमरा, लिविंग एरिया, किचन और यहां तक कि अटैच वॉशरूम भी होता है। वीडियो में आगे सिंगल बेड वाला अटैच बाथरूम का कमरा भी दिखता है। बोगी का वो वाला हिस्सा भी है जहां बैठकर अधिकारी पटरी का निरिक्षण करते हैं।

इंस्टाग्राम पर विकास गुप्ता (@vikasvivangupta) नाम के यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा कि 'भारतीय रेलवे निरीक्षण कोच।' अब तक इस वीडियो को 7 लाख 89 हजार के ऊपर व्यूज और 51 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। जबकि पोस्ट पर ढाई सौ से अधिक कमेंट्स भी आए है।

न्यूज विंडो

सीसी सड़क के बीच बना गैप बन रहा हादसों का कारण, फिसल रहे वाहन

गंजबासौदा। सिरोंज रोड स्थित गंज हनुमान मंदिर के समीप बनी सीसी सड़क के बीच छोड़ा गया गैप इन दिनों राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सड़क के बीच बने इस हिस्से में आए दिन दोपहिया वाहन चालक फिसलकर गिर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश के दौरान इस गैप में पानी भर जाने से इसकी गहराई दिखाई नहीं देती। ऐसे में वाहन चालक अनजाने में इस स्थान पर पहुंचते ही संतुलन खो बैठते हैं और सड़क पर गिर जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में यहां कई छोटे-बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक संबंधित विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। राहगीरों और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन एवं संबंधित विभाग से मांग की है कि सड़क के बीच बने इस गैप की शीघ्र मरम्मत कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार कार्य नहीं कराया गया तो कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है।

तीन साल का बेटा रोता रहा, पिता ने मां को पुल से दिया धक्का, घायल

रीवा। रीवा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पत्नी से चल रहे विवाद में आरोपी पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। जब पत्नी बच गई तो आरोपी पति ने पत्नी के गले पर शराब की केन से हमला किया, महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सोनौरी स्थित नैना नदी पुल की बताई जा रही है। इस पूरी घटना के दौरान तीन साल का बेटा भी मौके पर मौजूद था जो रोता रहा लेकिन निर्दयी पिता को बेटे या पत्नी किसी पर भी तरस नहीं आया। पुलिस ने आरोपी पति व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी सतीश पिता रमाशंकर 28 वर्ष निवासी शंकरगढ़ का अपनी पत्नी के साथ विवाद चलता था, इसी कारण पत्नी करीब दो साल से उससे अलग रह रही थी। कुछ दिन पहले ही पत्नी बेटे के साथ पंजाब से शंकरगढ़ अपनी सहेली के घर आई थी। उसे 28 जुलाई को वापस पंजाब जाना था, लेकिन वो ट्रेन चूक गई और इसी कारण उसने पति सतीश से प्रयागराज स्टेशन तक छोड़ने के लिए मदद मांगी थी। आरोपी पति सतीश पत्नी को प्रयागराज रेलवे स्टेशन छोड़ने का झांसा देकर शंकरगढ़ से बाइक में बेटे के साथ बैठाकर निकला। वो पत्नी व बेटे को प्रयागराज ले जाने के बजाए सोहागी होते हुए सोनौरी में स्थित नैना नदी पुल पर ले गया। 28 जुलाई की रात करीब 11 बजे प्लानिंग के तहत आरोपी पति ने पुल पर बाइक रोकी और पत्नी से विवाद करने लगा और इसी दौरान पत्नी को पुल से नीचे धक्का दे दिया। इसी दौरान आरोपी पति का एक साथी भी प्लानिंग के तहत मौके पर पहुंच चुका था। नदी में पानी कम होने के कारण महिला की जान बच गई और कुछ देर बाद वो जैसे-तैसे फिर से पुल पर चढ़कर वापस आई तो आरोपी पति ने जेब में रखी शराब की केन के नुकीले हिस्से से उसके गले पर हमला कर दिया और साथी के साथ मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद तीन साल का बेटा रो रहा था और इसी दौरान दो राहगीर अपनी-अपनी बाइक से पुल से गुजर रहे थे। राहगीर बच्चे को रोता देख रुके तो देखा कि महिला खून से लथपथ पड़ी है।

62 नामांतरण प्रकरणों का किया निराकरण, आवेदकों को मिली स्वीकृति

गंजबासौदा। नगर पालिका परिषद में शुक्रवार को आयोजित राजस्व विभाग की बैठक में नामांतरण से जुड़े 62 प्रकरणों का निराकरण करते हुए आवेदकों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया, जिससे आम नागरिकों को राहत मिली। बैठक के दौरान सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने कहा कि नगर पालिका द्वारा नामांतरण की प्रक्रिया को पहले की अपेक्षा अधिक सरल, पारदर्शी और सहज बनाया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं तथा नागरिकों को समय पर सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों से जनहित के अन्य राजस्व प्रकरणों का भी समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में राजस्व प्रभारी पार्षद नीलू चौबे सहित शुभम रघुवंशी, सरदार अहिरवार, नारायण, मनीष विश्वकर्मा तथा नगर पालिका के राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न राजस्व संबंधी विषयों पर भी चर्चा की गई और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।

पांच दिन की मासूम प्रिशा की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, मां ही निकली मासूम की कातिल

न हाथ कांपे, न दिल पसीजा! जिस बेटी को नौ माह कोख में पाला उसे ही पानी के ड्रम में डुबाया

सीधी। दोपहर मेट्रो

जिले से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक मां ने नौ महीने तक जिस बेटी को अपनी कोख में पाला उसे ही जन्म के पांच दिन बाद मार डाला। घटना चुरहट के भेलकी-820 गांव की है जहां गुरुवार को पानी के नीले ड्रम में मृत मिली 5 दिन की मासूम प्रिशा की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मासूम की हत्या की गई थी और हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि मासूम की मां ही निकली है। पुलिस ने बीते दिन आरोपी मां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

26 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में भेलकी-820 गांव में रहने वाले पंकज पटेल की पत्नी सोनू पटेल ने एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची का नाम प्रिशा रखा गया, 28 जुलाई को डॉक्टरों ने बच्ची और उसकी मां सोनू पटेल को स्वस्थ बताकर अस्पताल से छुट्टी दे दी और परिजन मां-बेटी को लेकर घर आ गए। प्रिशा ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, कि 30 जुलाई की सुबह उस वक्त सब कुछ बदल गया जब प्रिशा घर के सामने रखे पानी से भरे नीले ड्रम में मृत मिली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की तो पुलिस को मामला संदेहास्पद लगा।

परिवार में चौथी बेटी थी प्रिशा

प्रिशा माता-पिता की दूसरी बेटी थी और उनकी पहली बेटी करीब दो वर्ष की है। पिता पंकज पटेल के बड़े भाई की भी दो बेटियां हैं, इस तरह से संयुक्त परिवार में प्रिशा चौथी बेटी थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी पुलिस को हत्या की आशंका थी जो सच साबित हुई। चुरहट थाना प्रभारी रीता त्रिपाठी ने बताया कि मर्ग जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और बयानों के आधार पर नवजात की मां के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मामले की विवेचना जारी है।

ड्रम का ढक्कन बंद होने से गहराया शक

पुलिस के मुताबिक घटना के समय ड्रम का ढक्कन बंद था। पांच दिन की नवजात का खुद से ड्रम तक पहुंच पाना संभव नहीं था। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण और परिजनों के बयानों ने धीरे-धीरे घटनाक्रम की परतें खोल दीं। पुलिस ने मृतिका की मां, बड़ी मां और बुआ सहित अन्य परिजनों के बयान दर्ज किए तो प्रिशा की मौत का कारण पता चल गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रिशा की हत्या उसकी मां सोनू पटेल ने की थी। आरोपी मां सोनू पटेल नवजात बेटी के जन्म के बाद उसे पालने-पोसने को लेकर मानसिक रूप से परेशान थी। इसी कारण उसने 30 जुलाई की सुबह करीब 9.20 बजे बच्ची को घर के सामने रखे पानी से भरे नीले ड्रम में डुबो दिया और किसी को शक न हो, इसलिए ड्रम का ढक्कन भी बंद कर दिया।

अवैध हूटर, सायरन और वीआईपी स्टिकरों के खिलाफ अभियान शुरू

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

जिले में निजी वाहनों पर अवैध हूटर, सायरन, फ्लैशर लाइट, वीआईपी व शासकीय स्टिकर, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और काली फिल्म (ब्लैक फिल्म) लगाने वालों के खिलाफ पुलिस ने शनिवार से विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान 1 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेगा। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि अभियान के दौरान निजी वाहनों में लगे अवैध हूटर, सायरन, लाल, पीली और नीली फ्लैशर लाइट तत्काल हटवाई जाएगी। साथ ही ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निजी वाहनों पर लगाए गए वीआईपी, शासकीय, ड्यूटी पर अथवा अन्य विशेषाधिकार दर्शाने वाले स्टिकर, पदनाम, मोनोग्राम और प्रतीक चिन्ह पाए जाने पर भी कार्रवाई होगी। फैंसी, परिवर्तित, अस्पष्ट या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं बनी नंबर प्लेटों के खिलाफ भी सख्ती बरती जाएगी। चार पहिया वाहनों के शीशों पर नियमों के विपरीत लगी काली फिल्म मिलने पर भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना, विशेषाधिकार के झूठे प्रदर्शन पर रोक लगाना और यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। अभियान के दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा तथा सभी कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

चेकिंग अभियान: 53 वाहनों की जांच 2.78 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

धार। दोपहर मेट्रो

जिले में विशेष वाहन चेकिंग अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ह्रदेश यादव के नेतृत्व में परिवहन उप निरीक्षक सुश्री दिव्या पाटीदार, सहायक ग्रेड-2 श्री मधुकर सिसोदिया एवं उनकी टीम द्वारा बाग एवं कुक्षी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 53 स्कूल वाहनों की सघन जांच की गई। जांच में 15 वाहन विभिन्न नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित पाए गए, जिनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 2 लाख 78 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ह्रदेश यादव ने बताया कि जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही के उद्देश्य से इस प्रकार के विशेष जांच अभियान नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने वाहन संचालकों एवं शिक्षण संस्थानों से अपील की कि वे सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों एवं परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा यातायात नियमों का प्रभावी पालन कराने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

जब तक जीवन है, रामलला और जनता की सेवा करता रहूंगा- उमाकांत शर्मा

निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं पूर्ण विकास कार्यों का किया लोकार्पण

सिरोंज। दोपहर मेट्रो

रामलला सरकार मंदिर परिसर स्थित नवनिर्मित सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में विधायक उमाकांत शर्मा ने लगभग 1 करोड़ 2 लाख की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लगभग 36 लाख की लागत से पूर्ण हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर रामलला सरकार मंदिर समिति द्वारा विधायक उमाकांत शर्मा को रामलला सरकार का चित्र भेंट किया गया। जिसमें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि रामलला सरकार दीन-हीन नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के राजा हैं। रामलला के प्रति समाज की आस्था सदियों से बनी हुई है और उनकी पूजा-अर्चना विभिन्न कालखंडों में निरंतर होती

रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम ही हम सबके आराध्य हैं। उन्होंने कहा कि पद का अहंकार कभी स्थायी नहीं होता, समय का चक्र हर घमंड को चकनाचूर कर देता है। समाज अच्छे कार्य करने वालों का सम्मान करता है और गलत कार्य करने वालों का विरोध भी करता है। इस अवसर पर पार्षद रूपेश यादव ने कहा कि स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा रामलला सरकार के प्रति सदैव समर्पित रहे और मंदिर के प्रत्येक कार्यक्रम की चिंता करते थे। वे समय-समय पर फोन कर व्यवस्थाओं की जानकारी भी लेते रहते थे। कार्यक्रम में कैलाश सोनी, पदम ताम्रकार सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष मनमोहन साहू, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संतोष चौरे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दरयाव सिंह कुर्मी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सीताराम कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी ओम नारायण बड़कुल, नगरपालिका सीएमओ रामप्रकाश साहू, जनपद सीईओ आशीष अग्रवाल, मंदिर समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी की उपस्थिति रही इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन पार्षद तोषमणी पंथी ने किया। आरसीसी नाला निर्माण 68.29 लाख, एमपीईबी कार्यालय से कुशवाह समाज मंदिर तक रिन्यूवल कोट कार्य 20.31 लाख, रामलला मंदिर के द्वितीय तल पर सामुदायिक भवन निर्माण 10 लाख, रोहिलपुरा चाठोली मार्ग स्थित श्मशान घाट पर टीनशेड निर्माण - 3.62 लाख रुपए होगा।

नकली ऑफिसर बन लूट करने वाला आरोपी यूपी से गिरफ्तार

धार। दोपहर मेट्रो

बाग में नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठेकेदार राजकुमार मालवीय के घर से आधा किलो सोने के गहने और 4 लाख लूटने वाले गिरोह के मुख्य सरगना संजय शर्मा पंडित को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। यह वारदात 13 मार्च 2026 को हुई थी। इस सनसनीखेज डकैती में शामिल कुल 14 आरोपियों में से पुलिस पहले ही 10 को गिरफ्तार कर चुकी थी। बाग पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय शर्मा पंडित, जो माधवगढ़ (जिला जालौन, यूपी) का निवासी है, को जालौन से पकड़ा। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई एक पिस्टल भी जब्त की गई है।आरोपी को कुक्षी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

बाग थाना प्रभारी हीरूसिंह रावत ने बताया कि आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लुटेरों ने

बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी आईटी/सीबीआई ऑफिसर बनकर ठेकेदार के घर में छापा मारा था। जांच के बहाने अलमारी में रखे गहने व नकदी समेटकर आरोपी बाहर से ताला लगाकर भाग गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने ताला तोड़कर बाहर निकाला था। घटना के दो दिन बाद (16 मार्च को) पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से सोने के आभूषण, नकदी और वाहन सहित कुल 1.35 करोड़ की सामग्री जब्त की थी। जांच में सामने आया था कि ठेकेदार के घर में सोना और भारी नकदी होने की मुखबिरी स्थानीय तीन लोगों ने ही की थी।

तीन मंदिरों में हुई चोरी की वारदातों में चार सदस्यीय गिरोह को पकड़ा

नरसिंहपुर। दोपहर मेट्रो

नरसिंहपुर पुलिस ने जिले के तीन मंदिरों में हुई चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए चार सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। यह चोरियां करेली थाना क्षेत्र के सगौरिया जैन मंदिर, पलोहा थाना क्षेत्र के लिलवानी माता मंदिर और तेंदूखेड़ा के खेरापति मंदिर में हुई थीं। इन धार्मिक स्थलों पर हुई चोरियों के बाद से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था, जिससे पुलिस पर जल्द से जल्द खुलासे का दबाव बना हुआ था।पुलिस ने पंद्रह दिनों में इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए चोरी गया सामान बरामद किया है।

मेट्रो एंकर

नशे से दूरी है जरूरी 2.0% अभियान का समापन

युवाओं को नशामुक्त समाज बनाने का दिया संदेश

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

समाज को नशामुक्त बनाने और विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा चलाए गए 15 दिवसीय विशेष जन-जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 का पुलिस लाइन स्थित वेलफेयर हॉल में आयोजित समारोह के साथ समापन हुआ।

15 जुलाई से 30 जुलाई तक चले इस अभियान के समापन समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन, रक्षित निरीक्षक स्नेहा चंदेल, सूबेदार सूरज जमरा, ईशान रिछारिया, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन ने कहा कि नशे की लत केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के भविष्य को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग अपराध नियंत्रण के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता के ऐसे अभियानों को भी निरंतर आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों और नागरिकों से नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि अभियान का समापन अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। रक्षित निरीक्षक स्नेहा चंदेल ने पिछले 15 दिनों के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित जन-जागरूकता कार्यक्रमों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि नुक्कड़ नाटक, संवाद कार्यक्रम और जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से लोगों तक नशे के दुष्परिणामों का संदेश पहुंचाया गया। समापन समारोह में अभियान के तहत आयोजित चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन ने प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितजनों ने नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने का संकल्प लिया।

न्यूज विंडो

परियोजना की जनसुनवाई शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न

पाली/भिम्माडोंगरी। जे.के. सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित बेस्ट ऑफ शाहडोल (साउथ) कोल माइंस परियोजना की पर्यावरणीय जनसुनवाई ग्राम पंचायत भिम्माडोंगरी में शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान परियोजना से संबंधित सभी बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा ग्रामीणों के सुझावों और मांगों को गंभीरता से सुना गया। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का संचालन आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों से किया जाएगा। जे.के. सीमेंट लिमिटेड ने शून्य विस्थापन की नीति पर कार्य करने, प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा करने तथा कटने वाले प्रत्येक पेड़ के बदले 20 गुना अधिक वृक्षारोपण करने की प्रतिबद्धता दोहराई। कंपनी ने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार, कौशल विकास प्रशिक्षण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सड़क, पेयजल तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास का भी आश्वासन दिया। साथ ही ट्रस्क के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। जनसुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने परियोजना से जुड़े अपने सुझाव और अपेक्षाएं भी रखीं। अध्यक्षता कर रहे अधिकारियों ने कहा कि प्राप्त सभी सुझावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण कर पर्यावरण मंत्रालय एवं संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के खजवा गांव का मामला

छतरपुर में दिनदहाड़े खेत से रेत निकालने के विवाद में चली गोलियां, सात घायल

छतरपुर। दोपहर मेट्रो

छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के खजवा गांव में खेत से रेत निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट के बाद फायरिंग हो गई। घटना में एक पक्ष के चार और दूसरे पक्ष के तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत खेत के पास से रेत निकालने को लेकर हुई। पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते लाठी-डंडों और अवैध हथियारों से हमला तथा फायरिंग तक पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के दौरान कई राउंड गोलियां चलीं, जिससे एक पक्ष के चार लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के भी तीन लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। ग्राम खजवा निवासी घायल नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि उनके खेत से अवैध रूप से बालू निकाली जा रही थी। विरोध करने पर आरोपियों ने पहले धमकी दी और बाद में उनके परिवार पर हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हल्कईयां पटेल, बब्बू, देवीदीन, बल्लू, मुकुंदी, अरविंद, जितेन्द्र, रवि सहित कई लोग हथियारों के साथ पहुंचे और मारपीट करते हुए फायरिंग की। उनके अनुसार हल्कईयां और रवि ने कट्टों से गोली चलाई, जिसमें उनके भाई को गोली लगी। उन्होंने बताया कि उनके पिता, दोनों भाई और वह स्वयं घायल हुए हैं, जबकि महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। घायलों में पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा, धर्मदास विश्वकर्मा, नरेन्द्र विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा शामिल हैं।

30 से 35 लोगों के साथ गांव पहुंचे और हमला कर दिया

घायल पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा ने बताया कि जब उन्होंने खेत से बालू निकालने का विरोध किया तो आरोपी वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद करीब 30 से 35 लोगों के साथ गांव पहुंचे और हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों के पास लाठी, बका और अवैध कट्टे थे। मारपीट के दौरान चली गोली उनके पैर में लगी। उन्होंने बताया कि घटना में उनके पक्ष के चार लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं तथा पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि सुबह दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट की सूचना मिली थी। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति गोली चलाता दिखाई दे रहा है। दोनों पक्षों का मेडिकल कराया जा रहा है और चोटों की प्रकृति के आधार पर अपराध दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखाई दे रहे अवैध हथियारों के संबंध में भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद धाराएं तय कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक पक्ष के खेत के पास स्थित बरसाती नाले से दूसरा पक्ष रेत निकाल रहा था, हालांकि इस तथ्य की अभी पुष्टि की जा रही है।

कांग्रेस ने व्याप्त समस्याओं को लेकर किया विरोध-प्रदर्शन

नरसिंहपुर। दोपहर मेट्रो

शहर कांग्रेस कमेटी नरसिंहपुर द्वारा नगर पालिका की बिगड़ी कार्य प्रणाली, नगर में व्याप्त समस्याओं के निराकरण हेतु शुक्रवार को नरसिंहपुर नगर पालिका के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने नगर पालिका पर भ्रष्टाचार उदासीनता लापरवाही का आरोप लगाते हुए व्यापक नारेबाजी की । समस्याओं के निराकरण और कार्यप्रणाली सुधारने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

पूर्व विधायक सुनील जायसवाल ने अनेक आरोप लगाते हो कहा कि विपक्ष के नाते हम भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे। नगर में लगातार समस्या बढ़ती जा रही है जिससे नगर वासियों को अत्यधिक परेशानी हो रही है। नगर पालिका की घोर लापरवाही, उदासीनता के कारण विकास रुका हुआ है। जनपद अध्यक्ष शैलेंद्र राजपूत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण धनीराम पटेल ने कहा कि शहर के मुख्य मार्गों के अलावा नगर के सभी वार्डों में सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का आलम बना हुआ है । जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष विवेक पटेल ने कहा कि नगर पालिका के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जिला सेवादल अध्यक्ष अतुल चौरसिया ने कचरा ही कचरा पूरे शहर में दिख रहा है। सफाई न होने के कारण नालियां बजबजा रही हैं। जिला एनएसयूआई अध्यक्ष ईशान राय ने नगर पालिका पर अनेक आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका के कारण पूरा शहर परेशान है।

कांग्रेस प्रवक्ता आशीष गुप्ता एवं अजय दुबे ने कहा कि यदि जिम्मेदारी नहीं संभाल रही है तो नगर पालिका के भाजपा के जनप्रतिनिधियों को इस्तीफा दे देना चाहिए इसका नगरवासी स्वागत करेंगे। पूर्व पार्षद अजय मालवीय ने कहा कि नगर पालिका के जिम्मेदार अपने दायित्व निभाने से पूरी तरह से असफल हो गए हैं । शहर कांग्रेस अध्यक्ष रोहित पटैल ने विरोध प्रदर्शन में आए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीवर लाइन के कार्य के कारण सड़कें खराब हो गई है।

11 घंटे की मशक्कत के बाद बची चार युवकों की जान

खंडवा। दोपहर मेट्रो

बारिश के दौरान नदी किनारे सेल्फी लेना चार युवकों के लिए भारी पड़ गया। पिकनिक मनाने पहुंचे चार दोस्त अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से बीच में बने टापू पर फंस गए। गुरुवार शाम शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चला। ड्रोन के जरिए युवकों तक खाना, पानी और लाइफ जैकेट पहुंचाई गईं। करीब 11 घंटे की मशक्कत के बाद चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

खंडवा जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर सुक्ता और आबना नदी के संगम स्थित हांडीकुंडी पिकनिक स्पॉट पर शहर के मेडिकल व्यवसायी हुजेफा हामिद अली अपने साथियों असगर, मुस्तफा और मयंक के साथ घूमने गए थे। इसी दौरान क्षेत्र में हुई तेज बारिश से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और चारों युवक टापू पर फंस गए। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। युवकों को सुरक्षित निकालने के लिए गुरुवार शाम करीब छह बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि नदी में तेज बहाव के कारण शुरुआती प्रयास सफल नहीं हो सके। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम तैनात की और अतिरिक्त सहायता के लिए एनडीआरएफ को भी अलर्ट किया।

अनूपपुर जिले के 42 जर्जर शासकीय भवन, बारिश के बीच मंडरा रहा खतरा

अनूपपुर। दोपहर मेट्रो

जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच जर्जर शासकीय भवन लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। नगरीय निकायों द्वारा चिन्हित 51 जर्जर शासकीय भवनों में से अब तक केवल 9 भवनों को ही डिस्मेंटल (ध्वस्त) किया गया है, जबकि 42 जर्जर भवन आज भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। बारिश के चलते इन भवनों की दीवारें, छतों और अन्य संरचनाएं लगातार कमजोर होती जा रही हैं, जिससे इनके अचानक भरभराकर गिरने की आशंका बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में ऐसे भवनों की पहचान की गई थी, जिन्हें मानव जीवन के लिए असुरक्षित माना गया है। इसके बावजूद अधिकांश भवनों को हटाने की कार्रवाई अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे भवनों के आसपास रहने वाले लोगों और वहां से गुजरने वाले राहगीरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिन्हित जर्जर भवनों में सबसे अधिक 19 भवन अनूपपुर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित हैं। इनके अलावा अन्य नगरीय निकायों में भी कई भवन वर्षों से खस्ताहाल स्थिति में खड़े हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई भवनों के प्लास्टर और दीवारों के हिस्से पहले भी गिर चुके हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। हाल ही में कोतमा नगर में एक जर्जर भवन का हिस्सा अचानक गिर गया था। हालांकि उस घटना में बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह घटना प्रशासन के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार हो रही बारिश से ऐसे भवनों के गिरने का खतरा और अधिक बढ़ गया है। कई जर्जर भवन ऐसे स्थानों पर स्थित हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नया भोपाल संभाग लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म.प्र.)

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 11/व.ले.लि./निविदा/2026-27 भोपाल, दिनांक 28.07.2026

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

1	2	3	4	5	6
क्र	पोर्टल टेंडर क्रं.	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रं.	ठेके की अनु. राशि (रू.लाख में)	अमानत राशि
1	2026_PWDR B_524919_1	उपसंभाग क्रं.-2, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत सेक्शन क्रं.-9 स्थित शासकीय आवास गृहों में विभिन्न अनुरक्षण, साधारण मरम्मत, विशेष मरम्मत एवं डिपोजिट कार्य।	प्रथम आमंत्रण	19.90	39800.00
2	2026_PWDR B_524923_1	उपसंभाग क्रं.-2, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत विभिन्न शासकीय आवास गृहों में जल अवरोधक का कार्य।	प्रथम आमंत्रण	19.00	38000.00
3	2026_PWDR B_524929_1	उपसंभाग जेल-3, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत निर्माण भवन परिसर में राष्ट्रीय त्योहार के लिए आवश्यक और अनिवार्य व्यवस्थाओं से संबंधित साधारण मरम्मत कार्य।	प्रथम आमंत्रण	9.00	18000.00
4	2026_PWDR B_524933_1	उपसंभाग क्रं.-3, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत लिंक रोड एवं कोटरा सुल्तानाबाद रोड 150, 80, 60 फीट एवं अन्य मार्ग में सीमेंट कांक्रीट शोल्डर, नाली, सेन्ट्रल वर्ज मरम्मत, फुटपाथ, पेवर ब्लॉक, रोटरी नवीनीकरण एवं पेंच रिपेयर कार्य।	प्रथम आमंत्रण	15.00	30000.00
5	2026_PWDR B_524937_1	उपसंभाग क्रं.-3, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत मैन रोड नं. 3 में सीमेंट कांक्रीट शोल्डर, नाली, सेन्ट्रल वर्ज मरम्मत, फुटपाथ, पेवर ब्लॉक, रोटरी नवीनीकरण एवं पेंच रिपेयर तथा अन्य मरम्मत कार्य।	प्रथम आमंत्रण	15.00	30000.00
6	2026_PWDR B_524943_1	उपसंभाग क्रं.-3, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत मैन रोड नं 2 में सीमेंट कांक्रीट शोल्डर, नाली, रोन्ट्रल पर्ज मरम्मत, फुटपाथ, पेवर ब्लॉक, रोटरी नवीनीकरण एवं पेच रिपेयर तथा अन्य मरम्मत कार्य।	आमंत्रण प्रथम	15.00	30000.00
		योग:-		92.90	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) बेवसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय एवं सबमिशन करने की अंतिम तिथि 07.08.2026 सायं 5.30 बजे निर्धारित है। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर उसे उपरोक्त वेबसाईट पर देखा जा सकता है। विस्तृत एन.आई. टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइड में देखी जा सकती है।

'बच्चो की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखे हर हाल'

जी-16537/26 — कार्यपालन यंत्री नया भोपाल संभाग लो.नि.वि. भोपाल (म.प्र.)

मेट्रो एंकर — दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स संपन्न

व्यावहारिक प्रशिक्षण से पुलिस अधिकारियों की विधिक दक्षता हुई और अधिक सशक्त

सागर। दोपहर मेट्रो

पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में पुलिस कंट्रोल रूम, सागर में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का समापन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सोलंकी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इसमें जिले के विभिन्न थाना एवं इकाइयों से लगभग 70 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।

दो दिनों तक चले इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, अनुसंधान की नवीन प्रक्रिया, डिजिटल एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन, अपराध विवेचना, गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती, न्यायालयीन प्रक्रिया तथा कानूनों के व्यावहारिक क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर विस्तृत एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों ने नवीन कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया तथा केस स्टडी एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से कानूनों के प्रभावी अनुपालन की प्रक्रिया को समझाया। समापन अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि नवीन आपराधिक कानूनों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी, तकनीक आधारित, समयबद्ध एवं नागरिक-केंद्रित बनाना है। इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उनके प्रावधानों का गहन अध्ययन कर उन्हें व्यवहार में पूरी दक्षता के साथ लागू करें। सागर पुलिस द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि पुलिस बल को नवीन विधिक प्रावधानों, आधुनिक अनुसंधान तकनीकों एवं व्यावसायिक दक्षताओं से निरंतर अद्यतन रखा जा सके तथा आमजन को प्रभावी, संवेदनशील एवं गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल

क्रमांक/ /खनिज/2026 भोपाल, दिनांक / /2026

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (जो भी लागू हो) प्राप्त करने के लिए,

प्रथम सूचना

यह सुचित किया जाता है कि आवेदिका शमीम अफजल पुत्री श्री खान अफजल निवासी एफ-7 फर्स्ट फ्लोर गायेल काम्प्लेक्स नेहरू रोड बालविहार भोपाल म.प्र. द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 08.04.2026** को प्रस्तुत किया गया है। उक्त क्षेत्र पर प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस तक की अवधि तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन ई-खनिज पोर्टल **https://ekhanij.mp.gov.in** पर प्रस्तुत किये जायेंगें।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
भोपाल	बैरसिया	हिनौती सड़क	160, 161 एवं 162	मे से रकबा 3.000 हे.	शासकीय	पत्थर	भाग रकबा 3.000 हे.

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 05:30 बजे तक) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है-तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी (खनिज) जिला भोपाल

G-16499/26 — 'बच्चो की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखे हर हाल"

टीम इंडिया को बड़ी राहत

फिट हुए जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट में उतरने को तैयार

नई दिल्ली , एजेंसी

भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका दौरे से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है। टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट हो गए हैं और अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में उन्होंने सभी अनिवार्य फिटनेस टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं। इससे टीम प्रबंधन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि आगामी टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।

बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज के दौरान इम्पैक्ट इंजरी का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से उन्हें लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले से बाहर रहना पड़ा था। मेडिकल टीम ने एहतियात बरतते हुए उन्हें आराम दिया और उनकी फिटनेस पर लगातार नजर रखी। अब विस्तृत जांच और फिटनेस आकलन के बाद उन्हें पूरी तरह फिट घोषित कर दिया गया है। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, बुमराह ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा निर्धारित सभी शारीरिक और गेंदबाजी संबंधी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि वह श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलेंगे।

15 अगस्त से होगी अहम टेस्ट सीरीज

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। विदेशी परिस्थितियों में यह सीरीज भारतीय टीम के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज की वापसी तेज गेंदबाजी आक्रमण को नई धार देगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में भारत के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। फाइनल की दौड़ में मजबूती बनाए रखने के लिए टीम इंडिया को अपने शेष नौ टेस्ट मुकाबलों में कम से कम सात जीत दर्ज करनी होंगी। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीतना भारतीय टीम का प्रमुख लक्ष्य रहेगा। इसके बाद टीम को न्यूजीलैंड के कठिन विदेशी दौरे का भी सामना करना है, जहां मजबूत प्रदर्शन करना बेहद जरूरी होगा।

चोटों से जूझ रही टीम को मिली बड़ी राहत

हालांकि बुमराह की वापसी भारतीय टीम के लिए राहत की खबर है, लेकिन कई खिलाड़ी अब भी चोट के कारण बाहर हैं। तेज गेंदबाज हर्षित राणा हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे हैं, जबकि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी क्वाड्रिसेप्स की समस्या से जूझ रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग चोट के चलते पहले टेस्ट में उपलब्ध नहीं होंगे। वहीं तेज गेंदबाज आकाश दीप पीठ में स्ट्रेस रिएक्शन के कारण लंबे समय से टीम से बाहर हैं।

भगवा जर्सी पर हॉकी इंडिया में घमासान! अध्यक्ष दिलीप तिर्की बोले-

मेरी जानकारी के बिना लिया गया फैसला, बोर्ड से भी चर्चा नहीं

विश्व कप से पहले नई जर्सी पर विवाद गहराया

नई दिल्ली , एजेंसी

एफआईएच हॉकी विश्व कप से पहले भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम की नई भगवा जर्सी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल खुद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप तिर्की ने उठाया है। तिर्की ने दावा किया कि राष्ट्रीय टीम की पारंपरिक नीली जर्सी की जगह नया रंग अपनाने का फैसला उनकी जानकारी और हॉकी इंडिया की कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव बोर्ड से चर्चा किए बिना लागू कर दिया गया। उनके इस बयान के बाद महासंघ की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

बोर्ड को नहीं बताया

दिलीप तिर्की ने हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेजे ईमेल में कहा कि राष्ट्रीय टीम की पहचान से जुड़े इतने महत्वपूर्ण फैसले पर न तो बोर्ड में चर्चा हुई और न ही उन्हें पहले से इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति जर्सी के रंग को लेकर नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर है। उनके अनुसार, किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ में ऐसे फैसले निर्वाचित नेतृत्व और कार्यकारी समिति की सहमति से होने चाहिए।

तीन सवालों के जवाब मांगे

विवाद बढ़ने के बाद तिर्की ने हॉकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक कमांडर आर.के. श्रीवास्तव को निर्देश दिया कि सभी बोर्ड सदस्यों को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। उन्होंने तीन अहम सवालों के जवाब मांगे हैं—जर्सी का रंग बदलने की मंजूरी किसने दी, इस फैसले में कौन-कौन अधिकारी शामिल थे और अध्यक्ष व एग्जीक्यूटिव बोर्ड से सलाह क्यों नहीं ली गई।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

नई केसरिया जर्सी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे भारतीय हॉकी टीम की पारंपरिक पहचान से जोड़ते हुए सवाल उठाए, जबकि कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। हालांकि हॉकी इंडिया का कहना है कि नई जर्सी का डिजाइन पूरी तरह खेल और ब्रांडिंग से जुड़ा फैसला है तथा इसका किसी राजनीतिक उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है।

सरकार ने भी मांगी जानकारी

दिलीप तिर्की ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि इस विवाद को लेकर ओडिशा सरकार ने भी उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने हमेशा यही कहा कि खिलाड़ियों का ध्यान विश्व कप से न भटके, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया पर उठे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

विवादों में घिरा है हॉकी इंडिया

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब हॉकी इंडिया पहले से कई प्रशासनिक मुद्दों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहा है। हाल ही में महासंघ की उपाध्यक्ष असुंता लाकड़ा ने महासचिव भोला नाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने मामले की स्वतंत्र जांच कराने और आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी के पास भेजने के निर्देश दिए थे। ऐसे में जर्सी विवाद ने हॉकी इंडिया की प्रशासनिक पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्लास्गो में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन, कई खेलों में चमका तिरंगा

नीरज ने जीता सिल्वर, यशवीर को ब्रॉन्ज जूडो और डेकाथलॉन में भी रचा इतिहास

नई दिल्ली , एजेंसी

स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और यादगार दिन अपने नाम कर लिया। एथलेटिक्स, जूडो और मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाकर देश की झोली में कई पदक डाले। सबसे ज्यादा चर्चा पुरुषों की भाला फेंक (जेवलिन थ्रो) स्पर्धा की रही, जहां भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर अपनी शानदार वापसी का संकेत दिया, जबकि युवा खिलाड़ी यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीतकर भविष्य के बड़े सितारे के रूप में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की।

जेवलिन थ्रो में भारत का डबल मेडल

पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो पदक अपने नाम किए। अनुभवी एथलीट नीरज चोपड़ा ने सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 85.83 मीटर का थ्रो फेंका और रजत पदक हासिल किया। वहीं, युवा भाला फेंक खिलाड़ी यशवीर सिंह ने आखिरी प्रयास में 85.41 मीटर का शानदार थ्रो कर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीत लिया। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक श्रीलंका के रुमेश तरंगा पथिरागे ने 89.75 मीटर के शानदार थ्रो के साथ अपने नाम किया। उनका यह प्रदर्शन प्रतियोगिता के सबसे यादगार पलों में शामिल रहा।

आखिरी थ्रो में रोमांच, लेकिन फाउल ने रोक दी नीरज की उम्मीद

मुकाबले की शुरुआत में नीरज चोपड़ा बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन श्रीलंका के रुमेश पथिरागे के रिकॉर्ड थ्रो ने मुकाबले का पूरा समीकरण बदल दिया। अंतिम प्रयास में नीरज ने स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उनका आखिरी थ्रो फाउल हो गया। इसके बावजूद उन्होंने सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। नीरज और यशवीर का एक साथ पोडियम पर खड़ा होना भारतीय खेल इतिहास के लिए गर्व का पल बन गया। दोनों खिलाड़ियों ने तिरंगे के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया, जिसने भारतीय प्रशंसकों को भावुक कर दिया।

तेजस्विन शंकर ने रचा नया इतिहास | भारत के बहुमुखी एथलीट तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। वह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में डेकाथलॉन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दस अलग-अलग स्पर्धाओं में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए तेजस्विन ने अपनी फिटनेस, तकनीक और मानसिक मजबूती का बेहतरीन परिचय दिया। उनकी इस उपलब्धि को भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

जूडो में अस्मिता डे ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड | कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो से भी भारत के लिए ऐतिहासिक खबर आई। महिला जूडोका अस्मिता डे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया और कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत को जूडो का पहला गोल्ड मेडल दिलाया।

वैभव को उपकप्तान बनाने पर भड़के भोगले, बोले- आखिर सोच क्या है?

मुंबई। दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए ईस्ट जोन की टीम में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाए जाने का फैसला चर्चा का विषय बन गया है। युवा बल्लेबाज को ईशान किशन की कप्तानी वाली टीम का उपकप्तान बनाए जाने पर कई पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों ने हैरानी जताई है। मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले भी इस फैसले से सहमत नजर नहीं आए।

हर्षा भोगले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, %मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी को सीनियर रेड-बॉल टीम का उपकप्तान बनाने के पीछे क्या सोच रही होगी। उन्होंने 12 पारियों में 17.25 की औसत से 207 रन बनाए हैं। उनकी प्रतिभा असाधारण है, लेकिन रेड-बॉल क्रिकेट में अभी उनके सीखने की शुरुआत ही हुई है। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर तेजी से पहचान बनाई है। हालांकि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका अनुभव अभी काफी कम है। उन्होंने अब तक आठ प्रथम श्रेणी मैचों में 207 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 93 रन रहा है। ऐसे में दलीप ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उन्हें उपकप्तानी सौंपने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं।

ईशान किशन करेंगे कप्तानी

ईस्ट जोन टीम की कप्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को सौंपी गई है, जबकि वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान होंगे। बल्लेबाजी क्रम में वैभव के अनुभवी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन के साथ पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है।

मनोरंजन | **बॉलीवुड का कोना**

मैं चुड़ैल और वो गौरव जी क्यों?

लॉक अप में फूटा आकांक्षा का गुस्सा, श्रेया कालरा से तलाक पर हुई जबरदस्त भिड़ंत

मुंबई। रियलिटी शो लॉक अप में एक बार फिर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। इस बार विवाद की वजह बना आकांक्षा चमोला और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा के बीच हुआ तीखा टकराव। गौरव खन्ना के साथ अपने तलाक को लेकर कथित टिप्पणियों की जानकारी मिलने के बाद आकांक्षा ने श्रेया को जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने साफ कहा कि किसी के निजी रिश्ते और टूटी हुई शादी पर बिना सच्चाई जाने टिप्पणी करना बेहद असंवेदनशील और गलत है।

बहस के दौरान आकांक्षा ने श्रेया से सीधे सवाल किए कि आखिर वह गौरव खन्ना का सम्मान के साथ जिक्र करती हैं, जबकि उन्हें गलत तरीके से पेश किया जाता है। उन्होंने पूछा कि क्या श्रेया गौरव को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं या उनकी दोस्त हैं। आकांक्षा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना किसी रिश्ते की हकीकत जाने किसी एक पक्ष का समर्थन करना पूरी तरह अनुचित है। आकांक्षा ने आरोप लगाया कि उन्हें बताया गया था कि श्रेया ने कहा था कि उनका और गौरव का तलाक होना सही फैसला था क्योंकि वह गौरव के लायक नहीं थीं। इस कथित बयान पर आकांक्षा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि किसी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि किसी का रिश्ता सही था या गलत। उन्होंने श्रेया से पूछा कि आखिर वह उनके रिश्ते पर फैसला सुनाने वाली कौन होती हैं।

श्रेया ने किया इनकार

श्रेया कालरा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने आकांक्षा से अपील की कि दूसरों से सुनी हुई बातों पर भरोसा न करें। श्रेया ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य कभी भी आकांक्षा और गौरव के रिश्ते पर टिप्पणी करना नहीं था और उनकी बातों को गलत तरीके से समझा गया है। आकांक्षा ने कहा कि किसी की टूटी हुई शादी पर टिप्पणी करना बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने श्रेया से सवाल किया कि यदि कोई उनके निजी रिश्तों पर इसी तरह टिप्पणी करे तो उन्हें कैसा महसूस होगा।

मेट्रो बाजार

वर्ष 2029 तक एआई से निकाले गए निष्कर्ष बनेंगे निजता के लिए बड़ा खतरा

नई दिल्ली । वर्ष 2029 तक अधिकांश निजता (प्राइवेसी) से जुड़ी घटनाएं सीधे व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) की चोरी या लीक होने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा लोगों के बारे में निकाले गए निष्कर्षों (एआई-जेनरेटेडइन्फ्रेंसेज) के कारण होंगी। यह जानकारी रिसर्च एवं एडवाइजरी फर्म गार्टनर की एक नई रिपोर्ट में सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, जेनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग में तेजी से हो रही प्रगति के कारण साइबर हमलावर अब सामान्य, अनाम या एकत्रित डेटा से भी किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, व्यवहार संबंधी पैटर्न और अन्य संवेदनशील जानकारियों का अनुमान लगाने में सक्षम हो रहे हैं। यानी, भले ही किसी व्यक्ति का निजी डेटा सीधे लीक न हुआ हो, एआई उसके बारे में कई अहम निष्कर्ष निकाल सकता है।

गार्टनर के वाइस प्रेसिडेंट एनालिस्ट बार्ट विलेमसन ने कहा कि दुनिया अब डेटा एक्सपोजर से इनसाइट एक्सपोजर की ओर बढ़ रही है। अब तक कंपनियां मुख्य रूप से व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने पर ध्यान देती थीं, लेकिन एआई बिना पारंपरिक सुरक्षा तंत्र को तोड़े भी लोगों के बारे में बेहद निजी जानकारियों का अनुमान लगा सकता है। ऐसे में भविष्य में निजता से जुड़े जोखिम इस बात से अधिक पैदा होंगे कि एआई किसी व्यक्ति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालता है, न कि केवल कौन-सा डेटा सार्वजनिक हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनफरेंस अटैक विशेष रूप से खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन्हें पारंपरिक साइबर सुरक्षा प्रणालियों से पहचानना बेहद मुश्किल होता है।

101 करोड़ भारतीय अब सामाजिक सुरक्षा दायरे में, ईपीएफओ के डिजिटलीकरण पर फोकस : केंद्र

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने कहा कि भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के दायरे में अब करीब 101 करोड़ लोग, यानी देश की 68 प्रतिशत से अधिक आबादी शामिल है। इस उपलब्धि को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने भी सराहा है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि ऐसा संतुलित विकास मॉडल जरूरी है, जो एक ओर श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को आगे बढ़ाए, वहीं दूसरी ओर नियोक्ताओं के लिए कारोबार करने में आसानी भी सुनिश्चित करे।

राष्ट्रीय राजधानी में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स (एआईओई) और फिक्की की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित चौथे ग्लोबल इंडस्ट्रियल रिलेशंस समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औद्योगिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सरकार, उद्योग, नियोक्ता, श्रमिक और ट्रेड यूनियनों के बीच लगातार समन्वय आवश्यक है, ताकि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन साथ-साथ आगे बढ़ सकें।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास के लिए औद्योगीकरण बेहद जरूरी है, क्योंकि यह रोजगार सृजन को गति देता है। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सहकारी मॉडल, विशेषकर महिलाओं के नेतृत्व वाली पहलों की बढ़ती भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि ये आजीविका के अवसर बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। डॉ. मंडाविया ने रोजगार लोच में सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि अब जीडीपी में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि पर रोजगार में 1.11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, जबकि 12 वर्ष पहले रोजगार वृद्धि का यह आंकड़ा केवल 0.008 प्रतिशत था।

दयावान के किसिंग सीन पर फिर छिड़ी बहस! वर्षों बाद सामने आया नया दावा

डायरेक्टर की भूमिका पर उठे सवाल

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की चर्चित फिल्म %दयावान% का विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच फिल्माया गया किसिंग सीन आज भी सबसे विवादित दृश्यों में गिना जाता है। इस सीन को लेकर वर्षों से अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं। अब वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना के करीबी रहे ज्योति वेंकटेश ने इस पूरे विवाद पर अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि इस मामले में बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा और संभव है कि निर्देशक के निर्देशों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान ज्योति वेंकटेश ने कहा कि उनकी विनोद खन्ना से अच्छी मित्रता थी और उनके स्वभाव को देखते हुए उन्हें नहीं लगता कि अभिनेता ने जानबूझकर किसी तरह की जबरदस्ती की होगी। उन्होंने कहा कि यदि उस समय माधुरी दीक्षित के साथ वास्तव में कोई अनुचित घटना हुई होती और वह उसे सार्वजनिक रूप से उठाना चाहतीं, तो वह अपनी बात रख सकती थीं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उस समय सेट पर क्या हुआ था, इसकी प्रत्यक्ष जानकारी उनके पास नहीं थी।

निर्देशक की भूमिका पर जताया अनुमान

ज्योति वेंकटेश ने कहा कि उनके अनुसार इस पूरे विवाद में निर्देशक की भूमिका भी हो सकती है। उनका मानना है कि संभव है फिल्म के निर्देशक फिरोज खान ने दृश्य को उसी तरह फिल्माने के निर्देश दिए हों, जिसके कारण सीन अपेक्षा से अधिक लंबा चला। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह उनका व्यक्तिगत अनुमान है, क्योंकि वह शूटिंग के दौरान मौजूद नहीं थे और उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी।

पश्चिमी विदर्भ के ऊपर बने डिप्रेशन का असर, भोपाल समेत पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट; कई जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी

प्रदेश में 14 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, भारी बारिश व आंधी का अलर्ट जारी

नई दिल्ली. दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पश्चिमी विदर्भ और दक्षिणी मध्य प्रदेश के ऊपर बने मजबूत डिप्रेशन और सक्रिय मानसून ट्रफ के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग के अनुसार, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मंदसौर, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम और खरगोन में भारी बारिश का

अनुमान है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लगातार बारिश के कारण केंद्रीय हाइड्रोलॉजिकल विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के 14 जिलों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। निचले इलाकों, पुल-पुलियों और नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

राजधानी भोपाल में दिनभर बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। शहर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

राजधानी में ऐसा रहेगा मौसम

राजधानी भोपाल में शनिवार को पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, शहर में 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भोपाल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लोगों को बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

इन 14 जिलों में खतरा

लगातार बारिश के चलते आगर-मालवा, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम और शाजापुर जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग और केंद्रीय हाइड्रोलॉजिकल विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि छोटे नदी-नाले उफान पर आ सकते हैं और कई पुल-पुलियों के ऊपर से पानी बह सकता है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने की आशंका है।

प्रदेश के इन जिलों में भी बारिश और आंधी का अलर्ट

ग्वालियर दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, सतना, सीधी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग की जरूरी सलाह

बारिश और वज्रपात के दौरान खुले मैदान, बड़े पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। जलभराव वाले इलाकों और उफनते नालों को पार करने की कोशिश न करें। वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और खराब दृश्यता की स्थिति में अतिरिक्त सावधानी बरतें। प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर बनाए रखने की अपील की है।

नए ट्रेनिंग सेंटर और बढ़ते विमान बेड़े से बदल जाएगी भारतीय विमानन की तस्वीर

देश में खुलेंगे 11 नए फ्लाइंग स्कूल, 30 हजार से ज्यादा पायलटों की जरूरत

नई दिल्ली. एजेंसी

देश में तेजी से बढ़ रहे एविएशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए सरकार ने 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओ) शुरू करने की तैयारी की है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने फरवरी 2026 में जारी ई-टेंडर प्रक्रिया के तहत सात एयरपोर्ट पर 11 नए एफटीओ स्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य देश में पायलटों की बढ़ती मांग को पूरा करना है।

नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, अगले दस वर्षों में भारत को करीब 30 से 31 हजार अतिरिक्त पायलटों की जरूरत होगी। वहीं, अगले पांच वर्षों में एयरलाइंस कंपनियां अपने बेड़े में करीब 500 नए विमान शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा, देशभर में लगभग 50 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाने की भी संभावना है।

अप्रैल 2026 तक देश में महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) से मान्यता प्राप्त 41 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन 63 फ्लाइंग बेस से संचालित हो रहे हैं। नए संस्थान शुरू होने से घरेलू स्तर पर पायलट प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ेगी और छात्रों की विदेशों पर निर्भरता कम होगी।

शुरुआती चरण में इन नए एफटीओ में 60 से 70 प्रशिक्षण विमान शामिल किए जाएंगे, जो बाद में बढ़कर 110 से 120 तक पहुंच सकते हैं। शुरुआत में हर साल 400 से 500 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि पूरी क्षमता विकसित होने पर यह संख्या 1,500 तक पहुंच सकती है।

नए फ्लाइंग स्कूलों से छात्रों को होगा फायदा

नए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन शुरू होने से भारतीय छात्रों को पायलट प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने की जरूरत कम पड़ेगी। रीजनल एयरपोर्ट पर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होने से ट्रेनिंग अधिक सुलभ और किफायती होगी। इन संस्थानों में शुरुआती दौर में 60 से 70 प्रशिक्षण विमान तैनात किए जाएंगे, जो बाद में बढ़कर 120 तक पहुंच सकते हैं। पूरी क्षमता पर हर साल करीब 1,500 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश के विमानन क्षेत्र को कुशल मानव संसाधन भी मिल सकेगा।

अगले दशक में क्यों बढ़ेगी पायलटों की मांग

भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है। नागर विमानन मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, अगले दस वर्षों में देश को 31 हजार अतिरिक्त पायलटों की जरूरत होगी। एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस कंपनियां अपने बेड़े में नए विमान शामिल करने की तैयारी कर रही हैं। अगले पांच वर्षों में भारतीय एयरलाइंस करीब 500 नए विमान खरीद सकती हैं। इसके अलावा, देश में 50 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाने की योजना है। बढ़ते हवाई यातायात और नए रूट्स के कारण प्रशिक्षित पायलटों की मांग लगातार बढ़ रही है।

POK : रावलाकोट की घटना के बाद शाहबाज सरकार, सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

गिरफ्तारियों और इंटरनेट बंदी के विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन

इस्लामाबाद. एजेंसी

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के रावलाकोट में 27 जुलाई को हुए प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध की गूंज अब पूरे पाकिस्तान में सुनाई देने लगी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत कई बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार तथा सेना के खिलाफ नारेबाजी की।

जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के समर्थन में हुए इन प्रदर्शनों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और कथित दमन के खिलाफ आवाज उठाई गई। राजधानी इस्लामाबाद के एफ-10 इलाके में आयोजित रैली का नेतृत्व पूर्व सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने किया। उन्होंने रावलाकोट में हुई पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए मृतकों और घायलों के लिए न्याय की मांग की। प्रदर्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई), मानवाधिकार संगठनों और कश्मीरी समूहों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को बलपूर्वक दबाने की कोशिश कर रही है। उधर, लाहौर में प्रदर्शन से पहले प्रेस क्लब के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कई मार्गों को बंद कर दिया गया। इसके बावजूद विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने नागरिक अधिकारों, बेहतर प्रशासन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए सरकार से पुराने वादे पूरे करने की अपील की है।

रावलाकोट में हुई पुलिस कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद और लाहौर में लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया। इस्लामाबाद के एफ-10 इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इंटरनेट बंद कर नागरिकों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लाहौर में प्रदर्शन रोकने के लिए प्रेस क्लब के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

फिलिस्तीन, बलूचिस्तान और कश्मीर का मुद्दा भी उठा

प्रदर्शन में शामिल कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में अब फिलिस्तीन, कश्मीर और बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी खुलकर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार शांतिपूर्ण सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगाकर लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित कर रही है। उन्होंने रावलाकोट की घटना की निष्पक्ष जांच, बेहतर प्रशासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकार द्वारा किए गए पुराने वादों को पूरा करने की मांग की है। फिलहाल पूरे मामले पर पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

पत्नी की मौत के बाद दर्ज हुई एफआईआर

कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज

रोहतक. एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू उर्फ टिंकू बल्हारा की पत्नी मुस्कान बल्हारा की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतका के पिता सुखबीर की शिकायत पर बहुअकबरपुर थाना पुलिस ने शीलू बल्हारा, उसके पिता सुरेंद्र, मां निशा और भाई मनीष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और साजिश से जुड़े आरोपों में एफआईआर दर्ज की है।

फरमाणा गांव निवासी सुखबीर ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2023 में मुस्कान की शादी शीलू बल्हारा से हुई थी। उनका आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। परिवार के लोग मुस्कान को ताने देते थे कि वह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के स्तर के अनुरूप दहेज नहीं लाई है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मुस्कान को पति के कथित अन्य महिलाओं से संबंधों की जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। हालांकि, आरोपी पक्ष ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। मुस्कान के पिता का दावा है कि घटना वाले

दिन उनकी बेटी ने फोन कर अपनी जान को खतरा बताया था। बाद में जब वे ससुराल पहुंचे तो मुस्कान मृत अवस्था में मिली। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

बहुअकबरपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसबीर सिंह ने बताया कि मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर पति शीलू बल्हारा समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों से पूछताछ की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पिता ने लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप

मृतका के पिता सुखबीर का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही मुस्कान को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था। उन्होंने बताया कि कई बार परिवार ने कर्ज लेकर ससुराल पक्ष की मांगें पूरी कीं, लेकिन प्रताड़ना बंद नहीं हुई। सुखबीर के अनुसार, पंचायत स्तर पर भी समझौते की कोशिश की गई थी, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आया। उनका आरोप है कि मुस्कान को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था।

जैश के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड गिरफ्तार

हनीट्रैप में बंगाल के बड़े नेताओं को फंसाने का आरोप

कोलकाता. एजेंसी

संदिग्ध जैश-ए-मोहम्मद आतंकी हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने उसकी महिला मित्र अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ का दावा है कि अर्पिता केवल हमीम की परिचित नहीं, बल्कि पूरे संदिग्ध आतंकी माड्यूल की सक्रिय सदस्य थी। उसे ट्रांजिट रिमांड पर बर्द्धमान लाया गया है और अदालत से हिरासत लेकर दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि बंगाल एसटीएफ ने गुरुवार को पूर्व बर्द्धमान के एक आवासीय परिसर के जिस से हमीम मंडल को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ का दावा है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ, कुख्यात गैंग्सटर शहजाद भट्टी, पुलवामा हमले के आरोपित सज्जाद भट के नेटवर्क के संपर्क में था। जांच एजेंसी के अनुसार, हमीम और अर्पिता के बीच हुई कई वाट्सएप चैट से पूरे नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। चैट से यह भी संकेत मिले हैं कि दोनों को अलग-अलग 'असाइनमेंट' दिए जाते थे। एसटीएफ के अनुसार, सामान्य फोन कॉल के बजाय दोनों एक विशेष एन्क्रिप्टेड मोबाइल एप के जरिए संपर्क में रहते थे।

हिंद महासागर में भारत का 'मिशन शक्ति' 2530 किमी तक किसी की नहीं होगी एंट्री

चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच मध्यम दूरी की मिसाइल के परीक्षण की संभावना

नई दिल्ली. एजेंसी

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ओर से 2530 किलोमीटर के दायरे में जारी किए गए नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) ने रणनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। यह नोटिस 6 और 7 अगस्त के लिए जारी किया गया है। माना जा रहा है कि भारत इन तारीखों के दौरान मध्यम दूरी की किसी मिसाइल का परीक्षण कर सकता है।

आमतौर पर भारत बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में मिसाइल परीक्षण के लिए नोटम जारी करता है, लेकिन इस बार हिंद महासागर के उस क्षेत्र को चुना गया है, जहां हाल के वर्षों में चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। चीन अक्सर शोध और विकास (आरएंडडी) के नाम पर अपने जहाज और पनडुब्बियां इस क्षेत्र में भेजता रहा है। नोटम जारी होने के बाद संबंधित क्षेत्र में हवाई और समुद्री गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाई जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि 2530 किलोमीटर की दूरी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रेणी में आती है, इसलिए इस नोटिफिकेशन को संभावित मिसाइल परीक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक परीक्षण की पुष्टि नहीं की गई है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के नोटिस सुरक्षा और सामरिक तैयारियों का हिस्सा होते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी और सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो सकेगा कि नोटम का संबंध किसी सैन्य परीक्षण से है या किसी अन्य रणनीतिक अभ्यास से।

दोपहर मेट्रो हरिद्वार में 35 प्रशिक्षित साइबर कमांडो होंगे तैनात, 24 घंटे रहेगी निगरानी

कांवड़ मेले में होगी श्रद्धालुओं की डिजिटल सुरक्षा, साइबर कमांडो संभालेंगे कमान

देहरादून. एजेंसी

उत्तराखंड में पहली बार किसी बड़े धार्मिक आयोजन की साइबर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं। कांवड़ मेला-2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। इसे आगामी महाकुंभ-2027 की तैयारियों की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है।

पटेल भवन में कांवड़ मेले की ड्यूटी पर नियुक्त साइबर कमांडो की विशेष ब्रीफिंग आयोजित की गई। हरिद्वार में तैनात किए गए कमांडो को साइबर सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और रियल-टाइम इंटेलिजेंस से जुड़े दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि पहली बार इस स्तर की हाईटेक निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है। कांवड़ मेले के दौरान साइबर सिक्योरिटी यूनिट, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट, साइबर

इंटेलिजेंस यूनिट और इंसिडेंट रिस्पांस यूनिट चौबीसों घंटे सक्रिय रहेंगी। इनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों पर रोक लगाना, अफवाहों पर नियंत्रण रखना और श्रद्धालुओं की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देशभर से आए 31 प्रशिक्षित साइबर कमांडो और उत्तराखंड के चार विशेषज्ञ हरिद्वार कंट्रोल रूम, कांवड़ सेल और आईटीडीए में तैनात रहेंगे। यह टीम संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही फील्ड इकाइयों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगी। एसटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने ने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान मिलने वाला अनुभव महाकुंभ-2027 के लिए साइबर सुरक्षा की मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने में मददगार साबित होगा।

चार हाईटेक यूनिट संभालेंगी साइबर सुरक्षा की कमान

कांवड़ मेले में पहली बार चार विशेष साइबर इकाइयों को तैनात किया गया है। इनमें साइबर सिक्योरिटी यूनिट, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट, साइबर इंटेलिजेंस यूनिट और इंसिडेंट रिस्पांस यूनिट शामिल हैं। ये सभी टीमें चौबीसों घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइटों और अन्य डिजिटल माध्यमों पर नजर रखेंगी। इनका मुख्य उद्देश्य फर्जी खबरों और अफवाहों को रोकना, साइबर अपराधियों की पहचान करना और श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ठगी से बचाना है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत फील्ड अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके।

महाकुंभ-2027 की तैयारी का बनेगा आधार

अधिकारियों के मुताबिक, कांवड़ मेला-2026 में साइबर सुरक्षा का यह मॉडल आगामी महाकुंभ-2027 की तैयारियों का आधार बनेगा। एसटीएफ और साइबर विशेषज्ञ मेले के दौरान मिलने वाले अनुभवों का विश्लेषण करेंगे और भविष्य के लिए नई रणनीति तैयार करेंगे। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने सभी साइबर कमांडो को आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग करने और प्रत्येक साइबर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया** **स्थानीय संपादक अनिल शर्मा*** आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564